PRGI Reg. No. : CTHIN/25/A1911

हिन्दी दैनिक

लोकतंत्र प्रहरी

● वर्ष-01 ● अंक- 277 ● भिलाई, शुक्रवार 15 मई 2026 ● हिन्दी दैनिक ● पृष्ठ संख्या-8 ● मूल्य - 2 रुपया ● संपादक- संजय तिवारी, मो. 9200000214

जहां कभी एम्बुलेंस पहुंचना भी सपना था, वहां अब डॉक्टर दे रहे दस्तक : बस्तर के जंगलों तक पहुंची स्वास्थ्य क्रांति

दिल्ली में बस्तर विकास मॉडल पर मंथन शाह से मुख्यमंत्री साय की अहम मुलाकात

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बस्तर में तेजी से बदल रहे हालात और विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा उपस्थित थे। बैठक में विशेष रूप से बस्तर में चल रहे 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बताया कि जिन इलाकों में कभी एम्बुलेंस पहुंचना भी मुश्किल माना जाता था, वहां अब डॉक्टर, दवाइयां और स्वास्थ्य टीमें नियमित रूप से पहुंच रही हैं। दूरस्थ गांवों में पैदल जाकर लोगों की जांच की जा रही है और गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। मात्र एक महीने में 21.86 लाख से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है और उनके डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार कर लिए गए हैं। हजारों मरीजों को समय पर उपचार और उच्च अस्पतालों में रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर में अब पुराने सुरक्षा शिविर केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गए हैं। इन्हें धीरे-धीरे जन सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां गांव के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जरूरी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। इन केंद्रों के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहली बार कई बुनियादी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। ग्रामीण अब इलाज, बैंक खाते, दस्तावेज और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए दूर-दूर तक भटकने को मजबूर नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान की शुरुआत 13 अप्रैल 2026 से सुकमा से हुई है। इस अभियान में 36 लाख लोगों को लक्षित किया गया है। इसके अलावा बस्तर मुन्ने (अग्रणी बस्तर) अभियान के जरिए 31 महत्वपूर्ण योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। जगदलपुर में नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू हो गया है, जहां अब बस्तर के लोगों को महंगे इलाज के लिए रायपुर या बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा।

डायल-112 की नेक्स्ट जेन सेवा का विस्तार और पुराने सुरक्षा शिविरों को जन सुविधा केंद्र में बदलने की योजना भी बस्तर के स्थायी विकास की दिशा में अहम कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो इलाके कभी नक्सल प्रभाव के कारण मुख्यधारा से कटे हुए थे, वहां आज सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है।

हाल ही में सुकमा के एक अत्यंत दुर्गम गांव से गंभीर मरीज को सैकड़ों किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचाकर उपचार दिलाना इस बदलाव का बड़ा उदाहरण बना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को बस्तर के लिए तैयार विकास रोडमैप की जानकारी दी। इसमें सड़क, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से बस्तर में तेजी से सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर में हो रहे विकास कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की सराहना की।

देवास में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, कई घायल

देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिले में एबी रोड स्थित टोंककला क्षेत्र में संचालित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई। हादसे में कई मजदूरों के घायल होने की सूचना है, जबकि कुछ लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के मकानों तक में कंपन महसूस किया गया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी और भगदड़ का माहौल बन गया।

स्थानीय लोगों ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर घायलों को बाहर निकालने में मदद की। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए खुले में बारूद रखकर पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था। उनका कहना है कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थीं, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

ग्रामीणों में हादसे को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं फैक्ट्री को कथित राजनीतिक संरक्षण मिलने संबंधी चर्चाएं भी क्षेत्र में चल रही हैं, हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं तथा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच की जा रही है।

फैक्ट्री विस्फोट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जताया शोक

रायपुर। मध्य प्रदेश के देवास जिले में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दर्दनाक हादसे में हुई जनहानि को उन्होंने अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक बताया है। मुख्यमंत्री साय ने अपने शोक संदेश में कहा कि इस हादसे में दिवंगत हुए लोगों के प्रति वे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रभु श्रीराम से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवारों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही उन्होंने हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की।

केरल में सतीशन कांग्रेस विधायक दल के नेता

नयी दिल्ली। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन को पार्टी विधायक दल का नेता घोषित किया गया है।

कांग्रेस की केरल प्रदेश प्रभारी दीपादास मुंशी ने गुरुवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि श्री सतीशन को केरल में पार्टी विधायक दल का नेता बनाया गया है। इस मौके पर उनके साथ केरल के लिए नियुक्त किये गये केन्द्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक भी मौजूद थे। दास मुंशी ने बताया कि गत सात मई को तिरुवनंतपुरम में पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता चुनने का अधिकार पार्टी हाईकमान को दे दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में पार्टी के नेता राहुल गांधी, केन्द्रीय पर्यवेक्षकों तथा केरल के पार्टी सांसदों और अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किया। इस सब के बाद सतीशन का नेता पक्ष के लिए तय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि केरल में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधन (यूडीएफ) को 140 सीटों में से 102 सीटों के साथ दो तिहाई से अधिक बहुमत मिला है। पार्टी को राज्य में 10 वर्षों के बाद सरकार बनाने का मौका मिला है। इस जीत में सतीशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेता पक्ष की दौड़ में रमेश चेनीथल्ला, के सी वेणुगोपाल भी शामिल थे।

सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में होगा एसआईआर

नयी दिल्ली। आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के चरण-3 को 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया है।

चुनाव आयोग ने गुरुवार को बताया कि एसआईआर के चरण-3 को 16 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रही घर-घर सूचीकरण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आयोग ने बताया कि चरण-3 के तहत हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर लगभग पूरे देश को कवर किया जाएगा।

इन क्षेत्रों में मौसम और हिमपात की स्थिति को देखते हुए बाद में कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं से संपर्क करेंगे। उनके सहयोग के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट भी तैनात रहेंगे। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए नियुक्त करने की अपील की है, ताकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सहभागिता के साथ संपन्न हो सके। आयोग ने कहा कि पहले दो चरणों में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 59 करोड़ मतदाताओं को कवर किया गया था। जहां 6.3 लाख से अधिक बीएलओ और 9.2 लाख बीएलए विभिन्न चरणों में शामिल रहे। चरण-3 के कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन पांच जुलाई को होगा। जबकि अंतिम मतदाता सूची 06 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।

पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ने से अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति आठ प्रतिशत के पार

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण थोक बाजार में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में भारी उछाल के परिणामस्वरूप अप्रैल में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति की दर साढ़े तीन साल के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गयी।

अक्टूबर 2022 (8.39 प्रतिशत) के बाद पहली बार थोक महंगाई आठ फीसदी के पार दर्ज की गयी है। इससे पहले मार्च 2026 में थोक महंगाई दर 3.88 प्रतिशत रही थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 की तुलना में इस साल अप्रैल में पेट्रोल की थोक कीमत 32.40 प्रतिशत बढ़ गयी। डीजल की महंगाई दर 25.19 प्रतिशत और रसोई गैस (एलपीजी) की 10.92 प्रतिशत पर रही। कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस की थोक महंगाई दर 67.18 प्रतिशत दर्ज की गयी। इस वर्ग में कच्चा तेल 88 फीसदी महंगा हुआ। तिलहनों के दाम भी 22.24 प्रतिशत और खनिजों के 12.15 प्रतिशत बढ़े। खाने-पीने की चीजें सस्ती हुई हैं। आलू की कीमत एक साल पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत और टमाटर की 26 प्रतिशत घट गयी। दालें भी चार फीसदी सस्ती हुई हैं। अनाजों के दाम भी घटे हैं। सब्जियों के दाम में 0.53 प्रतिशत की मामूली सालाना वृद्धि दर्ज की गयी। फल 0.21 प्रतिशत सस्ते हुए। वहीं, अंडा, मांस और मछली के दाम 6.68 प्रतिशत और दूध के 2.56 प्रतिशत बढ़ गये। विनिर्मित वस्तुओं में कपड़ों की थोक महंगाई दर 7.30 प्रतिशत रही। तंबाकू उत्पाद 5.67 प्रतिशत महंगे हुए। रसायन और रसायन उत्पादों के दाम एक साल पहले के मुकाबले 5.09 प्रतिशत बढ़े।

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत, पंपों पर लगी लंबी कतारें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित होने से राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में ईंधन संकट गहराने लगा है। स्थिति यह है कि अनेक पेट्रोल पंपों का स्टॉक समाप्त हो चुका है, जबकि जहां सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध है वहां वाहन चालकों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। कई स्थानों पर निर्धारित सीमा में ही पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है।

जिले के करीब 13 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने की जानकारी सामने आई है। कई पंपों पर ''नो पेट्रोल'' और ''नो डीजल'' के बोर्ड लगाए गए हैं। शेष पंपों में सुबह से ही वाहनों की लंबी लाइनें लगी रहीं। ईंधन संकट का असर आम नागरिकों के साथ परिवहन सेवाओं, निजी संस्थानों तथा सरकारी विभागों पर भी दिखाई देने लगा है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में भी डीजल की भारी कमी दर्ज की गई है। अधिकांश पेट्रोल पंपों में डीजल समाप्त होने से परिवहन कारोबार प्रभावित हो रहा है। मालवाहक वाहनों के संचालन पर असर पड़ने लगा है और परिवहन व्यवसायियों में चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। महासमुंद शहर और आसपास संचालित आठ पेट्रोल पंपों में अधिकांश का स्टॉक खत्म हो चुका है।

केवल मचेवा स्थित शंकरा फ्यूल्स में सीमित मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होने से वहां वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं। जानकारी के अनुसार कई प्रमुख पेट्रोल पंप पहले ही बंद हो चुके हैं, जबकि अन्य पंपों का स्टॉक भी समाप्त हो गया है। सीमित उपलब्धता को देखते हुए दोपहिया वाहनों को दो लीटर तथा चारपहिया वाहनों को पांच लीटर तक ही ईंधन दिया जा रहा है। प्रदेश में ईंधन आपूर्ति बाधित होने से आम जनजीवन के साथ परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ने लगा है।

लोग जल्द आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद कर रहे हैं।

सुरक्षा परिदृश्य के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अब पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकती

तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकते : राजनाथ सिंह

नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय को मजबूत करने का आह्वान किया है और कहा है कि तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अब पुराने तरीकों पर निर्भर नहीं रह सकती। सिंह ने प्रमुख रणनीतिक संवाद 'कलम और कवच' में अपने वर्चुअल संदेश में कहा कि इस मंच का नाम ही देश के भविष्य के सुरक्षा ढांचे की सशक्त दृष्टि को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने कहा , कलम विचारों, तर्क और आगे की सोच रखने के साहस का प्रतीक है। कवच शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक है। जो देश स्पष्ट रूप से सोच सकता है और मजबूती से अपनी रक्षा कर सकता है, वही दुनिया में ऊंचा खड़ा होता है। हम ऐसे ही भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रहे हैं। वैश्विक संघर्षों के बदलते स्वरूप पर सिंह ने कहा कि दुनिया भर में रणनीतिक परिदृश्य लगातार अधिक अनिश्चित, प्रतिस्पर्धी और प्रौद्योगिकी-आधारित होता जा रहा है।उन्होंने भू-राजनीतिक तनाव, संघर्ष, साइबर खतरे, आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरी और हाइब्रिड युद्ध के उभरते स्वरूपों को देशों के सामने मौजूद प्रमुख चुनौती बताया। उन्होंने कहा, ऐसी दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा पुराने आयामों पर आधारित नहीं रह सकती। इसके लिए हमारी तैयारी, लचीलापन, नवाचार और रणनीतिक आत्मविश्वास आवश्यक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, जो राष्ट्र महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के लिए अत्यधिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, वह संकट के समय कमजोर बना रहता है। हमें अपने राष्ट्रीय तंत्र के भीतर ही प्रमुख प्रणालियों का डिज़ाइन, विकास, उत्पादन, रखरखाव और उन्नयन करना होगा। इसी तरह हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को सुरक्षित रख पाएंगे। रक्षा मंत्री ने विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया और कहा कि आधुनिक युद्ध में कई क्षेत्रों के बीच निरंतर समन्वय जरूरी है।

समय पूछने के बहाने महिला को चलती बस में खींचकर ले जाया गया, दो घंटे तक उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार

नयी दिल्ली। एक भयावह घटना ने राष्ट्रीय राजधानी को एक बार फिर झकझोर दिया है।

दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक चलती स्लीपर बस के अंदर 30 वर्षीय महिला का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई बस को जब्त कर लिया है और पीड़िता के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीतमपुरा की एक झुग्गी बस्ती निवासी पीड़िता और मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है। रात की शिफ्ट खत्म करने के बाद वह घर जा रही थी जब वह सरस्वती विहार के बी-ब्लॉक बस स्टैंड पर पहुंची। वहां एक स्लीपर बस खड़ी थी। जब उसने बस के दरवाजे पर खड़े एक युवक से समय पूछा, तो आरोपियों ने जवाब देने के बजाय उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया। पीड़िता के अनुसार, जैसे ही उसे बस में घसीटा गया, आरोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया और चालक को बस चलाने का निर्देश दिया। चलती बस के अंदर, दो लोगों ने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया। यह त्रासद घटना लगभग 7 किलोमीटर तक नांगलोई मेट्रो स्टेशन तक जारी रही। लगभग दो घंटे तक यौन उत्पीड़न करने के बाद, आरोपियों ने उसे खून से लथपथ हालत में रात करीब 2 बजे सड़क पर फेंक दिया। और फरार हो गए। हमले के तुरंत बाद पीड़िता ने पुलिस को फोन किया।

अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग की कार्रवाई
नदी में बना रैम्प काटकर किया गया अवरुद्ध

बलौदाबाजार। जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में तहसील लवन के ग्राम तिल्दा के महानदी में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा विगत गुरुवार को निरीक्षण किया। मौके पर अवैध उत्खनन या परिवहन होना नही पाया गया,लेकिन मौके पर उत्खनन करने के उद्देश्य से नदी में पहुंचने हेतु रैम्प का निर्माण होना पाया गया, जिसे जेसीबी मशीन से काटकर मार्ग अवरूद्ध किया गया,ताकि भविष्य में रेत की चोरी ना हो सके। जांच के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुरेश ठहरिया, विष्णु ठहरिया, चिंतामणी घृतलहरे, सत्या ठहरिया एवं दीप सिंह ठहरिया के द्वारा बताया गया कि गांव के सरपंच द्वारा प्रति ट्रेक्टर रेत भरने के एवज में 200 रुपए ट्रेक्टर चालकों से वसूल किया जाता है। जिस हेतु खनिज विभाग द्वारा छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत् सरपंच ग्राम पंचायत तिल्दा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया है। इसके पूर्व 29 अप्रैल को तिल्दा क्षेत्र का जांच किया गया, जांच के दौरान 4 नग मय रेत ट्राली सहित ट्रेक्टर नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,निकासी के दृष्टिकोण से रेत लोड करते पाये गये। उत्खननकर्ताओं के पास वैध खनिज अनुमति दस्तावेज, अभिवहन पारपत्र नही होने के फलस्वरूप वाहनों को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 (4) सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम-4(3) के तहत जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया जाकर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।

ईशान वैष्णव ट्रक मालिक संघ के जिला अध्यक्ष नियुक्त

बलौदाबाजार। जिला बलौदाबाजार भाटापारा के जिला स्तरीय ट्रक मालिक संघ की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा की सहमति पर जिला पंचायत के सभापति ईशान वैष्णव को ट्रक मालिक संघ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आहूत बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष एवं ट्रक मालिक संघ के संरक्षक अशोक जैन ने अध्यक्ष चयन प्रक्रिया में ईशान वैष्णव के नाम को प्रस्तावित किया गया जिस पर सभी ट्रक मालिक संघ के सदस्यों ने अपनी सहमति देते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर चयनित किया गया। ट्रक मालिक संघ जिला बलौदा बाजार भाटापारा के संरक्षक अशोक जैन, पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा, सुधीर अग्रवाल, गणेश जायसवाल, संजीव सिंह, सनोज सिंह ने संघ के नियमों एवं दिशा निर्देशों पर कार्य किए जाने का विश्वास व्यक्त करते हुए बधाई दी गई, व समय समय पर संघ द्वारा हितों के अनुरूप कार्य करने की बात भी कही गई। ट्रक मालिक संघ जिला बलौदा बाजार भाटापारा के नवनियुक्त अध्यक्ष ईशान वैष्णव को सर्व सम्मति से जिला अध्यक्ष नियुक्त किये जाने पर संघ के सदस्य गण एवं संरक्षकों ने पुष्प माला एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर अभिनंदन करते हुए बधाई दी गई, ट्रक मालिक संघ की आहूत बैठक में नाना देशमुख, धीरज साहू, अमित यादव, संतोष ठाकुर, राजू पारवानी, सुधीर जैन, मुकेश पंजवानी, भानु चंद्राकर,देवेंद्र वर्मा, बी.पी. साहू, राकेश ध्रुव, रवि साहू, मयूर जैन, ध्यानु गुप्ता, जितेंद्र सिंह, मनोज साहू, अमन सेन, शिरोज खान, जयंत यादव, प्रतीक जैन, के द्वारा नियुक्ति पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई।

जनसमस्या निवारण शिविर बना सुशासन और जनसेवा का सशक्त मंच
विधायक दीपेश साहू ने सुनीं आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश

बेमेतरा। आम जनता की समस्याओं के त्वरित निराकरण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा बेसिक स्कूल मैदान स्थित गांधी भवन में भव्य जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनसेवा का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा, जहां बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं और मांगें लेकर पहुंचे। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 01 से 07 तक के नागरिकों ने शिविर में भाग लेकर अपनी विभिन्न समस्याओं एवं आवश्यकताओं से प्रशासन को अवगत कराया। शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई, जिससे आमजन में संतोष और उत्साह देखने को मिला 7 कार्यक्रम मे विधायक साहू स्वयं शिविर में पहुंचे और आमजन की समस्याओं को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुना। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से आवेदनों के निराकरण की विस्तृत जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर त्वरित रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु है। ऐसे शिविरों के माध्यम से प्रशासन स्वयं जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहा है, जिससे लोगों का शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और मजबूत हो रहा है।

विभिन्न विभागों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र

शिविर में कार्यपालन अधिकारी, पुलिस विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, लीड बैंक, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, पशुधन विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सहित विभिन्न विभागों द्वारा जानकारी एवं सेवा शिविर लगाए गए। इन स्टॉलों के माध्यम से नागरिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। शिविर में नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए तथा बालिकाओं को पासबुक वितरित की गई।

सुशासन और जनकल्याण की दिशा में प्रभावी पहल

शिविर में वार्ड क्रमांक 01 से 07 तक के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। जनसमस्या निवारण शिविर जनसेवा, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी एवं सराहनीय पहल के रूप में सफल रहा।

जनता की सेवा ही हमारा संकल्प है : विधायक दीपेश साहू

शिविर को संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपने अधिकार और सुविधा के लिए भटकने को मजबूर न हो, यही सुशासन का मूल उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य किया जाए ताकि लोगों को त्वरित राहत मिल सके। विधायक साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और बुजुर्ग सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आम नागरिकों से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा किसी भी समस्या के लिए प्रशासन से सीधे संपर्क करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन का दायित्व है कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएं।

मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम के दौरान कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को विधायक दीपेश साहू द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा ही उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी कुंजी है और मेहनत, अनुशासन तथा लगन से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

जनता और शासन के बीच मजबूत हो रहा विश्वास : नगर पालिका अध्यक्ष

नगर पालिका अध्यक्ष सिन्हा ने भी शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि जनसमस्या निवारण शिविर शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त पहल से आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों से न केवल लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, बल्कि शासन के प्रति जनता का विश्वास भी लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए आमजन की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

सुशासन और जनकल्याण की दिशा में प्रभावी पहल
शिविर में वार्ड क्रमांक 01 से 07 तक के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। जनसमस्या निवारण शिविर जनसेवा, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन की दिशा में एक प्रभावी एवं सराहनीय पहल के रूप में सफल रहा।

ब्रह्मा कुमारीज़ ज्ञानांजलि भवन में हुआ नन्हें सितारें समर कैम्प का आयोजन

दल्लीराजहरा। ब्रह्मा कुमारीज़ ज्ञानांजलि भवन में 8 मई को नन्हें सितारें समर कैम्प का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया जिसमें दल्लीराजहरा की संचालिका ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा , और ब्रह्मा कुमारी स्वर्णा बहन, ब्रह्मा कुमारी आशा बहन,समाज सेवी छत्तीसगढ़ रत्न डॉक्टर शिरोमणि माथुर ,टी आर राणा डे ,गीता मरकाम ,गोपेश सोनवानी ,ब्रह्मा कुमारी प्रथा ,ब्रह्मा कुमारी मुस्कान इन सभी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। ब्रह्मा कुमारी पूर्णिमा ने बताया कि यह कार्यक्रम 8 मई से 14 मई तक चलेगा जिसका समय सुबह 9 बजे से 10 -30 बजे तक रहेगा जिसमें 5 वीं से वीं के सभी बच्चें भाग ले सकते है। इस समर कैंप में बच्चों को चित्रकला, नाटक, खेल, कविता, संगीत आदि सिखाया जाता है व्यक्तित्व विकास,बौद्धिक विकास, नैतिक मूल्य, चारित्रिक विकास इन सभी पर विशेष मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा।

खरीफ सीजन हेतु समितियों में 28899 मेट्रिक टन उर्वरक भण्डारित, डीएपी के वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग पर जोर

बलौदाबाजार। जिले में आगामी खरीफ सीजन के लिये समितियों में उर्वरक भण्डारण किया जा रहा है। जिले को यूरिया 42930, डीएपी 16500, पोटाश 3500, एसएसपी 8000 तथा एनपीके 14500 कुल 85430 मिट्रिक टन का उर्वरक लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध उर्वरक भण्डारण यूरिया 15390, डीएपी 3692, पोटाश 1859, एसएसपी 3994 तथा एनपीके 3964 कुल 28899 मिट्रिक टन हो चुका है। अब तक यूरिया 1660, डीएपी 392, पोटाश 1764, एसएसपी 233 तथा एनपीके 226 कुल 2553 मिट्रिक टन वितरण किया जा चुका है। जिले में उर्वरक भण्डारण वितरण का कार्य निरंतर जारी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार केवल डी.ए.पी. पर निर्भर रहना न केवल जोखिम भरा है, बल्कि इससे मिट्टी का संतुलन भी बिगड़ सकता है। बेहतर फसल उत्पादन और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित उर्वरकों का उपयोग बेहद जरूरी है। धान जैसी प्रमुख खरीफ फसल के लिए यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एन.पी.के. जैसे उर्वरकों का सही मात्रा में प्रयोग करना लाभकारी साबित होता है तथा डीएपी पर निर्भरता कम कर इसे वैकल्पिक उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही कृषकों को नील हरित काई, हरी खाद तथा जैव उर्वरक (बायो-फर्टिलाइजर्स) का उपयोग करने हेतु भी सलाह दिया गया है, जो की रासायनिक उर्वरको के निर्भरता पर कमी लाएगी।किसान बोरियों वाली खाद के स्थान पर नैनों यूरिया एवं नैनो डीएपी (तरल) को प्राथमिकता दें। यह न केवल परिवहन में आसान है बल्कि इसको उपयोग क्षमता 90 प्रतिशत तक है। इसके छिड़काव से फसल को सीधा पोषण मिलता है और जमीन भी खराब नहीं होती। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने बताया कि डी.ए.पी. की एक बोरी के बराबर पोषक तत्व अन्य विकल्पों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि 1 बोरी डी.ए.पी. के स्थान पर 3 बोरी एस.एस.पी. के साथ 20-25 किलो यूरिया, या 1.5 बोरी एन.पी.के. या 2 बोरी अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 1 बोरी टी.एस.पी. के साथ 2 बोतल नैनो यूरिया (500 मि.ली.) और 2 बोतल नैनो डी.ए.पी. (500 मि.ली.) भी प्रभावी विकल्प हैं।

चिकन पॉक्स एवं उल्टी दस्त के मामले की सूचना तत्काल देने निर्देश

सरायपाली। स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में बीएमओ कुणाल नायक ने टीकाकरण से लेकर सुशासन तिहार तक दिए गए अहम दिशा-निर्देश सुशासन तिहार के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से समस्त सुपरवाइजर एवं एलएचवी की ऑनलाइन बैठक बीईटीओ टी.आर. धृतलहरे द्वारा आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सुशासन तिहार के दौरान बिना पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के कोई भी अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। वहीं एमआर अभियान अंतर्गत 23 मई से 31 मई 2026 तक छूटे हुए हितग्राहियों का शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन सुनिश्चित करने कहा गया। एचपीवी वैक्सीन को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि वैक्सीन केवल मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति एवं अभिभावकों की सहमति से ही लगाया जाएगा। साथ ही खाली पेट, बुखार, एलर्जी अथवा अस्वस्थ बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाने तथा बाएं हाथ के डेल्टाइड मसल्स में आईएम के रूप में लगाने के निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। बैठक में चिकन पॉक्स एवं उल्टी-दस्त के मामलों की तत्काल सूचना देने, वीएचएनडी सत्र सुबह 8 बजे से प्रारंभ करने तथा सभी लाभार्थियों की यू-विन पोर्टल में शत-प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने कहा गया। वैक्सीनेशन पूर्व ड्यू लिस्ट तैयार करने, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट एवं बैच नंबर रजिस्टर में दर्ज करने तथा ओपन वायल पॉलिसी का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। फील्ड भ्रमण के दौरान मितानिनों की दवा पेटी जांचने, प्रत्येक सप्ताह एक रूका निरीक्षण कर रिपोर्ट ब्लॉक कार्यालय में जमा करने तथा एनसीडी स्क्रीनिंग एवं रि-स्क्रीनिंग की लंबित एंट्री पूर्ण कराने पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा एमडीआर एवं सीडीआर ऑडिट इस माह पूर्ण कराने, कुष्ठ एवं टीबी मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध कराने तथा सीएचओ द्वारा टीबी मरीजों का प्रत्येक 15 दिन में गृह भ्रमण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में सभी सुपरवाइजर एवं एलएचवी को अपने-अपने सेक्टर के आम में उपलब्ध टैबलेट एवं लैपटॉप की स्थिति तथा रिचार्ज संबंधी जानकारी इस सप्ताह उपलब्ध कराने कहा गया। संस्थागत प्रसव, जन्म-मृत्यु पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र एवं जेएसवाय फॉर्म किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रखने के निर्देश भी दिए गए।

डिकेश्वर वर्मा को बलौदाबाजार प्रेस क्लब ने दी श्रद्धांजलि

बलौदाबाजार। समाचार पत्र वितरक डिकेश्वर वर्मा का आकस्मिक निधन हो गया। वे पिछले लगभग 40 वर्षों से सर्दी, गर्मी और बारिश जैसी हर परिस्थिति में निरंतर बलौदाबाजार शहर में अखबार वितरण का कार्य करते आ रहे थे। उनके निधन से पत्रकारिता जगत एवं शहरवासियों में शोक व्याप्त है। डिकेश्वर वर्मा को याद करते हुए बलौदाबाजार प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां उपस्थित पत्रकारों एवं सदस्यों ने दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा उनके योगदान को स्मरण किया। प्रेस क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि डिकेश्वर वर्मा केवल समाचार वितरक नहीं थे, बल्कि वे प्रतिदिन पाठकों तक सही समय पर समाचार पहुंचाने वाले एक सच्चे कर्मवीर थे। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समाचार सेवा को समर्पित कर दिया। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष नरेश गनशानी, उपाध्यक्ष दिलीप महेश्वरी, सचिव दलजीत सिंह चावला, सहसचिव विजय तिवारी, कोषाध्यक्ष राजेश्वर गिरी, राघवेंद्र सिंह, गोविन्द राते, राजकुमार बलेचा, श्रवण ध्रुव, प्रीतलाल कुर्रे, पुष्पकांत मेजर, आभाष शर्मा, मोहित मरकाम, तुलसी साहू, राजू पाल, किशोर बंजारे सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता बेमेतरा का बारहवीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन

बेमेतरा। बेमेंतरा जिले व दाढ़ी क्षेत्र के एकमात्र सीबीएसई विद्यालय डी ए वी मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जांता बेमेतरा ने बारहवीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने शानदार अंक प्राप्त कर न केवल विद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम गौरवान्वित किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही विद्यालय परिसर में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण निर्मित हो गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं। विद्यालय के प्राचार्य पी एल जायसवाल ने परीक्षा में सफल सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह परिणाम विद्यार्थियों की निरंतर मेहनत, अनुशासन, लगन एवं विद्यालय के गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि विद्यालय सदैव विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उत्कृष्ट शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहा है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में विद्यालय के विद्यार्थियों ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। विद्यालय के शीर्ष तीन विद्यार्थियों में उदयप्रकाश ने 91.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं आदित्य देवांगन ने 84.8 प्रतिशत अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान तथा गणेश निर्मलकर ने 75.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में विशेष उत्साह का माहौल देखा गया। विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी। साथ ही विद्यालय परिवार ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में भी विद्यार्थी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय एवं क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते रहेंगे।

ईंधन बचत, गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाए : अंकिता मिश्रा

धमतरी। पश्चिम एशिया युद्ध के असर के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते युद्ध तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और कीमतों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन रही है। ऐसी स्थिति में देश में संभावित पैट्रोल, डीजल एवं कमर्शियल गैस संकट को ध्यान में रखते हुए योगेश फाउंडेशन की संस्थापक एवं समाज सेविका अंकिता रत्नेश मिश्रा सहित उनके टीम के समस्त सदस्यों ने देश हित में एक सराहनीय निर्णय लेते हुए 17 मई को स्पेशल बस के द्वारा स्कूली बच्चों को राजिम, आरंग एवं अन्य पर्यटन स्थलों के पूर्व निर्धारित सामूहिक भ्रमण कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। फाउंडेशन के संस्थापक अंकिता मिश्रा एवं उनके सहयोगियों ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में देश के संसाधनों पर अतिरिक्त भार न पड़े, इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। इसी भावना से फाउंडेशन ने सामूहिक भ्रमण एवं व्यक्तिगत अन्य स्थानों के भ्रमण तथा अन्य गैर जरूरी खर्चों में भी कटौती करने का निर्णय लिया है। देश जब चुनौती पूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा हो तब प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संयम और जिम्मेदारी का परिचय दे। ईंधन की बचत और गैर जरूरी खर्चों में कटौती करके हम राष्ट्र के प्रति अपना कर्त्तव्य निभा सकते है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील भी की कि वे डीजल, पेट्रोल एवं गैस का उपयोग अति आवश्यक कार्यों तक सीमित रखें, अनावश्यक यात्रा से बचे तथा ऊर्जा सरंक्षण के माध्यम से देश की आर्थिक मजबूती में सहयोग करें।

तारुण्य वार्ता हैशटैग पीरियड्स पर खुलकर अभियान का हुआ आगाज

धमतरी। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के अंतर्गत तारुण्य वार्ता हैशटैग पीरियड्स पर खुलकर.. अभियान के साथ ही दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यूनिसेफ और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन हो रहा है। रायपुर स्थित श्री बालाजी विद्या मंदिर में मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करने राज्य के सभी जिलों से तीन. तीन की संख्या में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के जिला संगठन आयुक्त एवं लीडर्स जुटे हैं। जिला धमतरी से जिला संगठन आयुक्त गाइड हीना भेंसले की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि की आसंदी से छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा वर्णिका शर्मा ने कहा कि मासिक धर्म पर चुप्पी नहीं, जागरूकता और संवाद की आवश्यकता है। हर बेटी को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहवारी प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने यूनिसेफ और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान की प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने कहा कि यूनिसेफ के साथ शुरू की गई मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की इस मुहिम को पूरे छत्तीसगढ़ में हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 28 मई को अभियान का समापन मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में होगा। यूनिसेफ की छत्तीसगढ़ हेड सीमा कुमार ने कहा कि यह गर्व की बात है कि आज हम लड़कियों की गरिमा, समानता और स्वास्थ्य सुरक्षा का अभियान शुरू कर रहे हैं। यह बालिकाओं के सशक्तिकरण का भी अभियान है। उन्होंने कहा कि यह अभियान माहवारी के मिथकों और अनावश्यक पाबंदियों को तोड़ने का काम करेगा। यह अभियान लड़कियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह लड़कों को भी माहवारी के प्रति जागरूक करेगा और उनकी समझ को बढ़ाएगा तथा झिझक को दूर करेगा। सीमा कुमार ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन जैसे विषय को स्कूलों के पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाने की मांग रखी। यूनिसेफ के व्यवहार परिवर्तन स्पेशलिस्ट अभिषेक सिंह ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस अभियान से माहवारी को लेकर किशोरों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता में वृद्धि होगी। मासिक धर्म स्वच्छता व्यवहार में सुधार आएगा और इस विषय पर बात करने की झिझक दूर होगी तथा भ्रांतियों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान बालिकाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर देगा। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान यूनिसेफ की बाल संरक्षण विशेषज्ञ चेतना देसाई, वाश स्पेशलिस्ट श्वेता पटनायक, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय आयुक्त जी स्वामी, रेडक्रास सोसायटी के उपाध्यक्ष रूपेश पाणिग्रही, राज्य मुख्यालय आयुक्त रविश गुप्ता, स्टेट कोऑर्डिनेटर मेंबरशिप ग्रोथ मोहम्मद सादिक शेख भी मंचासीन रहे। शुभारंभ कार्यक्रम का संचालन राज्य प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट पूनम सिंह साहू ने किया तथा आभार राज्य संयुक्त सचिव बीना यादव द्वारा जताया गया। पहले दिवस का प्रशिक्षण यूनिसेफ के एसबीसी कंसलटेंट अभिषेक त्रिपाठी, वाश ऑफिसर बिरजा कबी सतपथी, आशिष कुमार द्वारा प्रदान किया गया। दो दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का संयोजन दिलीप पटेल द्वारा किया जा रहा है। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की राज्य प्रशिक्षण आयुक्त गाइड सरिता पाण्डेय, राज्य संगठन आयुक्त द्वय अमित क्षत्रिय, जलवती साहू सहित अन्य की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन का संकल्प भी दिलाया। अतिथियों द्वारा पोस्टर का विमोचन भी किया गया।

संक्षिप्त समाचार

चाकू दिखाकर युवक से 10 हजार की लूट, एक आरोपी पकड़ाया

रायपुर। राजधानी में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी और गंभीर आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में टिकरापारा पुलिस ने चाकू दिखाकर युवक से लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।मामले में प्रार्थी विशाल सोनकर ने 10 मई 2026 को थाना टिकरापारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 8 मई की शाम वह ई-स्कूटी से कुशालपुर से शंकर नगर जा रहा था। शाम करीब 5:30 बजे साहू कॉम्प्लेक्स गोंडवाना भवन के पास सिगरेट पीने के दौरान बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने हाथ-मुक्का और डंडे से मारपीट शुरू कर दी।पीड़ित के मुताबिक दो आरोपी उसकी स्कूटी पर बैठ गए और चाकू दिखाकर धमकाते हुए उसे सिद्धार्थ चौक स्थित एटीएम तक ले गए। वहां से आरोपियों ने जबरन 10 हजार रुपये निकलवाकर लूट लिए और मौके से फरार हो गए।घटना की शिकायत पर टिकरापारा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 119(1), 308(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 के तहत अपराध दर्ज किया।पुलिस उपायुक्त संदीप पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा एवं सहायक पुलिस आयुक्त न्यू राजेंद्र नगर के निर्देशन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। लगातार दबिश और पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी विशाल बृजवानी उर्फ दीनू को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी की पहचान विशाल बृजवानी उर्फ दीनू (26 वर्ष) निवासी नंदी चौक टिकरापारा, हाल मुकाम गोकुल नगर नंबर-05 थाना टिकरापारा के रूप में हुई है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

लक्ष्य ज्वेलरी शॉप में चोरी करने दो गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी के बीच शहर दरमियानी रात दो नकाबपोश चोरों ने लक्ष्य ज्वेलर्स को निशाना बनाया। दोनों बाइक से आए और कटर से ताला काटकर भीतर घुस गए। करीब आधे घंटे में सोने के जेवर बैग में भरकर फरार हो गए। रविवार को दुकान बंद थी, इसलिए चोरी का पता सोमवार सुबह चला। दुकान खुलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर नॉर्थ जोन के अधिकारी और पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला पहुंचे। दुकान के सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपी आराम से चोरी करते नजर आए हैं। चोरी गए जेवर की कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। देर रात पुलिस ने कालीनगर से पुराने चोर को हिरासत में लिया है। दावा है उसने ही अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की है। पुलिस के अनुसार, शंकर नगर-लोधीपारा रोड पर आरोग्य अस्पताल के पास कारोबारी वंश मरपानी का लक्ष्य ज्वेलरी दुकान है। शनिवार रात 8 बजे दुकान बंद की गई थी। रविवार को अवकाश के कारण बंद रही। सोमवार सुबह खोलने पर चोरी का पता चला। कॉम्प्लेक्स में 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात रहता है और आसपास अस्पताल होने से लगातार आवाजाही रहती है, इसके बावजूद किसी को भनक नहीं लगी। चोरों ने चांदी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हाथ नहीं लगाया। चोरी की सूचना मिलते ही फोरेंसिक और डॉग स्क्वॉड की टीम मौके पर पहुंची। डॉग दुकान से दौड़ते हुए निकला और करीब डेढ़ किलोमीटर दूर गांधी नगर-काली नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर जाकर ठिठक गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच शुरू की। देर रात पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लिया। उसके पास से सोने के जेवर भी बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। दोनों आदतन चोर हैं और पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल कालीमाता वार्ड में किराए से रह रहे थे और मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। फरार साथी की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि उसके पकड़े जाने पर अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।

राजधानी में बंदूक-चाकू की नोक पर फल विक्रेता से 36,600 रुपये की लूट

रायपुर। राजधानी रायपुर के मोदहापारा थाना क्षेत्र में देर रात बंदूक और चाकू की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। फल बेचकर घर लौट रहे एक युवक को उसके परिचित ने तीन साथियों के साथ मिलकर सुनसान गली में रोक लिया और मारपीट कर 36 हजार 600 रुपये लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, मोदहापारा निवासी शेख साहिल बांबे मार्केट में फल का ठेला लगाता है। सोमवार रात करीब 10:20 बजे वह रोज की तरह दुकान बंद कर दिनभर की कमाई लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान तालाबपार स्थित महतो गैरेज के पास फिरोज कबाड़ी गली में उसका सामना पिता के पुराने परिचित राजा बैसड़ से हुआ।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

शासन बना बेटियों का संबल और सामूहिक विवाह बना सामाजिक बदलाव का उत्सव....

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में इन दिनों जब भी सामूहिक विवाह समारोहों में शहनाइयां गूंजती हैं, तो वह केवल दो लोगों के वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर नहीं होता, बल्कि समाज में समानता, सम्मान और संवेदनशील शासन व्यवस्था का जीवंत उत्सव बन जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व में यह योजना प्रदेश में सामाजिक बदलाव की नई इबारत लिख रही है। हजारों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाली यह पहल वास्तव में बेटियों के साथ सुशासन का आशीर्वाद बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने हजारों गरीब परिवारों की चिंताओं को कम करते हुए बेटियों के सपनों को नई पहचान दी है। यह योजना आज प्रदेश में सामाजिक समरसता, महिला सम्मान और जनकल्याण का ऐसा मॉडल बन चुकी है, जिसने यह साबित किया है कि शासन की योजनाएं यदि संवेदनशील सोच के साथ लागू हों, तो वे सीधे लोगों के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बेटियों का विवाह अक्सर आर्थिक चिंता का बड़ा कारण बन जाता है। कई बार परिवार कर्ज लेने को मजबूर होते हैं, तो कई बार सामाजिक दबाव और फिजूलखर्ची उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कर देती है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई। योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि विवाह को गरिमामय, सादगीपूर्ण और सामाजिक सहयोग का माध्यम बनाना है। यह योजना सामूहिक विवाहों को बढ़ावा देकर दहेज जैसी कुरीतियों पर भी प्रभावी रोक लगाने का काम कर रही है। राज्य शासन ने योजना को और अधिक मानवीय स्वरूप देते हुए विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी इसमें शामिल किया है, इससे यह योजना सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशीलता की मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कार्डधारी परिवारों की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को लाभ प्रदान किया जाता है।प्रत्येक कन्या विवाह हेतु शासन द्वारा अधिकतम 50 हजार रुपये तक सहायता दी जाती है। इसमें वर-वधु के लिए श्रृंगार सामग्री, उपहार सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही 35 हजार रुपये की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में दी जाती है, जिससे नवदंपति आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपने नए जीवन और खुशहाल की शुरुआत कर सकें। विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं पर भी प्रति कन्या 8 हजार रुपये तक खर्च किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 24 हजार से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है। यह केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं, बल्कि उन हजारों परिवारों की खुशी और राहत की कहानी है, जिनके लिए बेटियों का विवाह कभी बड़ी चिंता हुआ करता था। प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 3200 विवाहों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 347 विवाह पहले ही संपन्न हो चुके थे, जबकि 8 मई 2026 को आयोजित राज्यव्यापी सामूहिक विवाह समारोहों में 1385 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे।

आईआईआईटी में डिजिटल दक्षता एवं एआई एकीकरण पर चरणबद्ध प्रशिक्षण सम्पन्न

- शासकीय कार्यों में दक्षता एवं उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष जोर
- 100 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रशिक्षण में की सहभागिता

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में डिजिटल उत्पादकता एवं एआई एकीकरण विषय पर चरणबद्ध एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डिजिटल दक्षता बढ़ाना, प्रशासनिक कार्यों में तकनीक आधारित कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी से उपयोग के प्रति जागरूकता विकसित करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में कार्यालयीन कार्यों में दक्षता वृद्धि, त्वरित निर्णय प्रक्रिया, दस्तावेज निर्माण, सूचना संक्षेपण एवं कार्य निष्पादन को अधिक प्रभावी बनाने में डिजिटल तकनीकों एवं एआई टूल्स की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर डॉ. ओ.पी. व्यास द्वारा विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक सत्र संचालित किए गए। उन्होंने जनरेटिव एआई के उपयोग, उसकी संभावनाओं एवं सीमाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में उसकी उपयोगिता पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एआई मानव बुद्धिमत्ता का सहयोगी उपकरण है, जिसका उपयोग कार्यों को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने में किया जा सकता है। प्रशिक्षण का प्रमुख आकर्षण इंटरैक्टिव एवं हैंड्स-ऑन सत्र रहे, जिनमें प्रतिभागियों ने विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में एआई टूल्स का व्यावहारिक उपयोग किया।

हल्की बारिश का असर कम होते ही उमस से लोग परेशान

- पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से जारी बदली और हल्की बारिश का दौर कमजोर पड़ते ही एक बार फिर गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। मौसम में नमी बढ़ने के कारण दिनभर चिपचिपी गर्मी का एहसास बना रहा। मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में सोमवार को दिनभर तेज धूप के साथ उमस का असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान में करीब 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर के समय सड़कों पर गर्म हवाओं और उमस के कारण लोगों को काफी परेशानी हुई। सोमवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की वर्षा हुई। बीजापुर जिले के दोपनापाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क बना रहा, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। सबसे ज्यादा गर्मी राजनांदगांव में रिकॉर्ड की गई, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।

सुशासन तिहार बना ग्रामीण महिलाओं की नई ताकत हाटी शिविर में स्थानीय उत्पादों की धूम

4755 तालाब हुए लबालब

नहरों से सूखते तालाबों में जल भराव भीषण गर्मी से बड़ी राहत

- मुख्यमंत्री साय की मंशा के अनुरूप सूखते तालाबों को जीवनदान देने जल संसाधन विभाग का विशेष अभियान

रायपुर/ संवाददाता

वर्तमान में भीषण गर्मी के दौरान तालाबों में पानी की कमी से जूझ रहे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में सूख रहे 4 हजार 755 तालाबों को अब तक विभाग द्वारा त्वरित पहल करते हुए नहरों के माध्यम से भरा जा चुका है और जरूरत के मुताबिक शेष तालाबों में भी पानी भरने का कार्य तेजी से जारी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भीषण गर्मी ने पूरे देश को अपने चपेट में ले रखा है, इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। इससे जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्र में पानी का प्रमुख स्त्रोत तालाब भी जलविहीन हो रहे हैं। ऐसे हालात में लोगों को राहत पहुंचाने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में सूख रहे तालाबों में जल भराव का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें सर्वाधिक रायपुर जिला के अंतर्गत निस्तारी हेतु प्रस्तावित कुल 783 तालाबों में से अब तक 663 तालाबों में जल भराव हेतु नहर से पानी दिया जा चुका है।

हाथी के हमले में जान गंवाने वाले ग्रामीणों के परिजनों को त्वरित राहत

रायपुर। महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशों पर जिला प्रशासन और वन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए सूरजपुर जिला के कल्याणपुर में हाथी हमले के शिकार हुए हितग्राहियों के परिजनों को मुआवजा राशि का वितरण कर दिया है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि पीड़ित परिवारों को बिना किसी विलंब के सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर निवासी दो ग्रामीणों की हाथी हमले में मृत्यु होने के पश्चात, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (सूरजपुर मंडल) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की गई। विभागीय दस्तावेजों के अनुसार, दोनों प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजा राशि स्वीकृत कर वितरित की गई है, जिनमें हितग्राही श्रीमती कांति भोई को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 5 लाख 50 हजार रूपए एवं श्रीमती राजेश्वरी सिंह श्याम को डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में 5 लाख 50 हजार रूपए भेज दी गई है।

निगम में टैंकर भुगतान में करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप

रायपुर। संवाददाता

निर्धारित टेंडर राशि से अधिक भुगतान का दावा, महापौर ने जांच के दिए संकेत रायपुर। नगर निगम रायपुर में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई के ठेकों को लेकर वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारीने आरोप लगाया है कि पिछले दो वर्षों में निर्धारित टेंडर राशि से कहीं अधिक भुगतान किया गया, जिससे करोड़ों रुपये के घोटाले की आशंका है।दस्तावेजों का हवाला देते हुए विपक्ष का दावा है कि वर्ष 2025 में लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के टेंडर के विरुद्ध करीब 3.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं 2024 में 50 लाख रुपये के टेंडर के मुकाबले लगभग 1.68 करोड़ रुपये का भुगतान होने की बात कही गई है।जोनवार भुगतान के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में टैंकरों की संख्या और भुगतान राशि में बड़ा अंतर सामने आया है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में शामिल छह कंपनियों ने समान दर पर निविदा भरी और सभी को एल-1 मानते हुए ठेका दे दिया गया।विपक्ष द्वारा जिन कंपनियों के नाम सामने रखे गए हैं, उनमें मेसर्स केशव प्रसाद पांडेय, प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन, परिमल कश्यप, अरविंद सिंह ठाकुर, प्रवीण दीक्षित और रफीक अहमद शामिल हैं।नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने सवाल उठाया कि कई वर्षों से इन्हीं कंपनियों को लगातार ठेका कैसे मिल रहा है और सभी के रेट तथा आवेदन की तारीख समान कैसे हो सकती है।

सुशासन तिहार किसानों को दे रहा संबल और समाधान

सुशासन तिहार में किसानों को एचपी का विद्युत पंप प्रदान किया

रायपुर/ संवाददाता

सुशासन तिहार के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं अब धरातल पर प्रभावी रूप से साकार होती नजर आ रही हैं। किसानों और अन्नदाताओं को नई ऊर्जा, मजबूत संबल एवं कृषि क्षेत्र को विकास की नई दिशा मिल रही है। सरकार की पहल से ग्रामीण जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का संचार हो रहा है। कोरबा के ग्राम गिधौरी के 52 साल के किसान श्री दीनदयाल यादव को भी अपनी समस्या का समाधान सुशासन तिहार के तहत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में मिला। श्री यादव खेती के साथ-साथ सिलाई कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके पास लगभग दो से ढाई एकड़ कृषि भूमि है, जहां वे खेती कार्य करते हैं। खेती ही परिवार की आजीविका का मुख्य साधन होने के बावजूद सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से उन्हें लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। परिवार की जिम्मेदारियों और बच्चों के पालन-पोषण के बीच खेती को बेहतर बनाने की उनकी इच्छा लगातार बनी हुई थी। सुशासन तिहार के शिविर में उनकी समस्या को गंभीरता से समझते हुए कृषि विभाग द्वारा उन्हें 1.5 एचपी का विद्युत पंप प्रदान किया गया। लगभग 15 हजार 875 रुपये मूल्य के इस विद्युत पंप से अब उनके खेतों में सिंचाई कार्य सुगमता से हो सकेगा तथा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। विद्युत पंप मिलने से श्री यादव के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। इससे शासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक मजबूत हुआ। श्री यादव ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझते हुए उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रही है। खेती में सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सुशासन तिहार के माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण होने से अब खेती कार्य सुगम हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शासन की यह पहल किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और लाभकारी साबित हो रही है, जिससे न केवल कृषि कार्यों को नई गति मिल रही है, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

सुशासन तिहार बना ग्रामीण महिलाओं की नई ताकत

सुशासन तिहार 2026 अब केवल समस्याओं के समाधान का मंच नहीं रह गया है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के सपनों, हुनर और आत्मनिर्भरता को नई पहचान देने वाला अभियान बनता जा रहा है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम हाटी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में इसका जीवंत स्वरूप देखने को मिला, जहां महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल आकर्षण का केंद्र बने रहे। शिविर में गांव की महिलाओं ने अपने हाथों से तैयार पारंपरिक और घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई।

संपादकीय

महिला आरक्षण पर दावे बड़े, हकीकत छोटी ?

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। देश की सभी पार्टियां राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का एक मत से समर्थन करती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के लिए तैंतीस फीसद आरक्षण का विधेयक पारित कराने में भी सभी दलों की भूमिका रही। मगर महिलाओं की नुमाइंदगी के सवाल पर संजीदा दिखने वाली लगभग सभी पार्टियां क्या तब तक इस मुद्दे पर ठोस पहल नहीं करेंगी, जब तक विधायिका में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहार में लागू न हो जाए?आखिर क्या वजह है कि देश में लोकसभा या फिर विधानसभा के लिए जब भी चुनाव होते हैं, तो उसमें पर्याप्त संख्या में महिलाओं को टिकट देने को लेकर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता है? गौरतलब है कि चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों की ओर से जितनी महिलाओं को टिकट दिया गया और उनमें जीतने वालों की जो संख्या रही, वह महिला भागीदारी के सवाल पर राजनीतिक दलों के प्रचारित सरोकार के प्रति ईमानदारी को कठघरे में खड़ा करती है।दरअसल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में हुए चुनाव के दौरान कुल आठ सौ चौबीस सीटों पर चुनाव हुए। उनमें जीत हासिल करने वाली महिलाओं का अनुपात बेहद कम रहा। नतीजों के मुताबिक, इन पांचों प्रदेशों में कुल पांच फीसद सीटों पर ही महिलाएं चुनी गईं। इन राज्यों में अलग-अलग पार्टियों ने महिलाओं को टिकट देने में भी अपने घोषित सरोकारों के उलट रवैया अपनाया। मसलन, पश्चिम बंगाल में दो सौ सात सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आने वाली भाजपा ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन उसने सिर्फ तैंतीस सीटों पर महिलाओं को मौका दिया था।जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपनी उम्मीदवारी के 291 सीटों में से 52 महिलाओं को टिकट दिया था। नतीजतन, राज्य की कुल सीटों में से सिर्फ दस फीसद महिलाएं जीत सकीं। दूसरी ओर, तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ, जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके 234 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन उसने सिर्फ चौबीस महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। असम में फिर से जीतने वाली भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 126 सीटों में से केवल छह महिलाओं को टिकट दिया। केरल में जीत हासिल करने वाली यूडीएफ ने सिर्फ दस महिलाओं को मौका दिया।जाहिर है, तकरीबन सभी पार्टियों ने महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। हालांकि हाल ही में संसद में परिसीमन विधेयक पारित न होने के संदर्भ में महिला आरक्षण का सवाल चुनावी राजनीति का भी मुद्दा बना और भाजपा की ओर से इस मसले पर विपक्षी दलों पर सवाल उठाए गए। विडंबना यह है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के घोषित दावों के बरक्स टिकट देने के मामले में भाजपा सहित सभी पार्टियों के भीतर इच्छाशक्ति की कमी दिखती है।

अस्पताल या इंतजार केंद्र? इलाज से पहले ही थका देती है व्यवस्था, बिस्तरों की कमी ने बढ़ाई मुश्किल

देश के अस्पतालों में प्रति एक हजार लोगों के लिए औसतन 1.3 बिस्तर हैं, जबकि दुनिया का मानक इससे दोगुने से भी ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि मरीज ज्यादा हैं और जगह कम है। अस्पताल उपचार का केंद्र होते हैं, लेकिन कई बार वे खुद ही बीमार नजर आते हैं। यह कहने और सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन देश के स्वास्थ्य तंत्र की इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। जिन स्वास्थ्य संस्थानों पर हम जीवन बचाने का भरोसा करते हैं, वही कई बार संसाधनों की कमी, प्रबंधन की विफलता और बढ़ती व्यावसायिकता की वजह से संकट का कारण बन जाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा दबाव है, या फिर इसे खुद इलाज की जरूरत है।

(मनीष जैसल)

आज के दौर में अस्पताल जाना कई बार बीमारी से बड़ा अनुभव बन जाता है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन सबसे पहले उसे भीड़ और कतार में खड़े होकर कई घंटे इंतजार करने की परेशानी से जूझना पड़ता है। इसके बाद कहीं बिस्तर नहीं मिलता, तो कहीं विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद नहीं होते। यही नहीं, कई बार सब कुछ होने के बावजूद व्यवस्था साथ नहीं देती। यह तस्वीर किसी एक शहर की नहीं, बल्कि देश भर की है।

देश के अस्पतालों में प्रति एक हजार लोगों के लिए औसतन 1.3 बिस्तर हैं, जबकि दुनिया का मानक इससे दोगुने से भी ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि मरीज ज्यादा हैं और जगह कम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या और साफ दिखती है, जहां आबादी इतनी ज्यादा है कि अस्पताल हमेशा भरे रहते हैं। समय के साथ आबादी बढ़ी, मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसके अनुरूप अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल (एनएचपी-2022) के अनुसार, देश में प्रति दस हजार आबादी पर अस्पतालों में बिस्तर की उपलब्धता लगभग पंद्रह है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार न्यूनतम संख्या तीस बिस्तरों की है। यानी हम बुनियादी स्तर पर अभी आधे रास्ते में हैं। राज्यों के बीच असमानता इस संकट को और गहरा करती है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वास्थ्य सेवाएं अपेक्षाकृत बेहतर हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। बिहार में प्रति दस हजार आबादी पर बिस्तरों की संख्या छह-सात के बीच है। इसका मतलब है कि एक ही देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता नागरिक की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करती है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस 2022-23) की रपट से पता चलता है कि देश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के 70 फीसद से अधिक पद खाली हैं। कई बड़े राज्यों में यह आंकड़ा 75-80 फीसद तक है। यानी ग्रामीण भारत में रहने वाले करोड़ों लोग प्राथमिक स्तर पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं से वंचित हैं।

अस्पतालों में संक्रमण की स्थिति भी चिंताजनक है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, देश में 10-15 फीसद मरीज इलाज के दौरान ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। विकसित देशों में यह आंकड़ा लगभग आधा है। यानी हमारे अस्पताल कई बार रोग से मुक्ति के बजाय नई बीमारी का केंद्र बन जाते हैं। कोविड-19 महामारी ने इस सच्चाई को सबके सामने रखा। आक्सीजन की कमी, गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों का अभाव और अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ये दृश्य केवल एक आपदा नहीं, बल्कि हमारी तैयारियों की कमी का परिणाम थे।

निजी अस्पतालों की भूमिका भी सवालों से परे नहीं है। इलाज की बढ़ती लागत और पारदर्शिता की कमी ने आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को महंगा एवं जटिल बना दिया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 65 फीसद और शहरी क्षेत्रों में 70 फीसद लोग निजी अस्पतालों का सहारा लेते हैं। यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर घटते भरोसे का संकेत है।

देश में चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:1400 के आसपास है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और खराब है। नर्सिंग स्टाफ की कमी और उपकरणों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। कैग की रपटों में पाया गया है कि कई अस्पतालों में महंगे उपकरण या तो खराब पड़े रहते हैं या उनका उपयोग नहीं हो पाता। यानी समस्या संसाधनों की कमी के साथ-साथ उनके प्रबंधन की भी है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 700 टन से अधिक जैव-चिकित्सीय कचरा उत्पन्न होता है, जिसका पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो पाता। यह स्थिति संक्रमण के खतरे को और बढ़ाती है।

इन चुनौतियों के बीच वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य था- गरीब और कमजोर वर्ग को पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना। यह योजना अपनी अवधारणा में बेहतर थी और इसने लाखों लोगों को पहली बार बड़े अस्पतालों तक पहुंचने का अवसर दिया। मगर जैसे-जैसे इसका विस्तार हुआ, वैसे-वैसे इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आने लगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की जांच में पाया गया कि कई अस्पतालों ने फर्जी मरीज दिखाकर या अनावश्यक प्रक्रियाएं जोड़कर इस योजना के तहत धनराशि के दावे किए। ऐसे मामलों में सैकड़ों निजी अस्पतालों को अनियमितताओं के कारण इस योजना से बाहर कर दिया गया।

ऐसे मामलों का मानवीय पक्ष अधिक असहज करता है। एक सीमित आय वाला परिवार आयुष्मान कार्ड के भरोसे निजी अस्पताल पहुंचता है और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। सतह पर सब कुछ सामान्य दिखता है, मगर बाद में कई बार सामने आता है कि अस्पताल की ओर से मरीज के इलाज के दौरान जिन प्रक्रियाओं का दावा किया गया, वे हुई ही नहीं। यानी अस्पतालों के लिए उपचार की गुणवत्ता से इतर, खर्च के बिल का विस्तार प्राथमिकता बन जाता है।

देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता भी स्पष्ट दिखाई देती है। लगभग 65 फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सकों का बड़ा हिस्सा शहरों में केंद्रित है। इस प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बर्बादी के साथ-साथ कई बार मरीज की स्थिति भी गंभीर हो जाती है।

दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अत्यधिक भीड़ और दबाव के कारण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह असमानता केवल सुविधा की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच के अभाव को दर्शाती है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित होता है, जबकि सरकारी अस्पतालों पर गरीब और निम्न आय वर्ग की निर्भरता अधिक है। अनुमानतः 60 से 70 फीसद मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं, जहां सुविधाएं अपेक्षाकृत बेहतर होती हैं, लेकिन खर्च अधिक होता है।

इसके विपरीत, सरकारी अस्पतालों में इलाज सस्ता या निःशुल्क होता है, लेकिन वहां संसाधनों की कमी और अत्यधिक भीड़ के कारण मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति एक ऐसी दोहरी व्यवस्था को जन्म देती है, जहां इलाज की गुणवत्ता व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है और यह स्वास्थ्य सेवाओं की समानता और न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। ऐसे में अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और मानव संसाधनों की कमी को दूर करना प्राथमिक कदम होने चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

7,900 मौतें, 80 हजार लापता- प्रवासन का छिपा वैश्विक संकट जो बदल रहा दुनिया का चेहरा

(देवेंद्रराज सुथार)

प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक रपट ने विश्व समुदाय का ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित किया है, जो अक्सर राजनीतिक बहसों और सीमा सुरक्षा की चर्चाओं के पीछे छिप जाता है। रपट के अनुसार, वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक प्रवास के दौरान मारे गए या गायब हुए लोगों की कुल संख्या 80 हजार से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल उन मामलों की है, जो दर्ज हो सके। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। इन आंकड़ों का अर्थ यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग बेहतर जीवन, सुरक्षा या रोजगार की तलाश में ऐसी यात्राएं कर रहे हैं, जिनका अंत अक्सर शोषण या गुमनामी में होता है।

प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है। इसलिए प्रवासन के सवाल को केवल कानूनी या अवैध प्रवेश के दायरे में सीमित करना सही नहीं है। इसे मानवीय गरिमा, श्रम अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही कारण है कि यह रपट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

प्रवासन मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है। लोग सदियों से जल, भूमि, व्यापार, सुरक्षा और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। आधुनिक युग में प्रवासन के स्वरूप अधिक जटिल हो गए हैं। आज इसे व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है- आंतरिक प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवासन में लोग अपने ही देश के भीतर गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या पिछड़े क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में लोग दूसरे देशों की सीमाएं पार करते हैं। आर्थिक प्रवासी वे लोग होते हैं, जो बेहतर रोजगार और आय के लिए जाते हैं, जबकि शरणार्थी वे हैं, जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

आज प्रवासन संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी आव्रजन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। वीजा नियमों की जटिलता, सीमित श्रम कोटा, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव लाखों लोगों को अनियमित मार्गों की ओर धकेलते हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर, सहारा रेगिस्तान, अमेरिका-मेक्सिको सीमा, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में बदल चुके हैं। लोग छोटी और असुरक्षित नौकाओं में समुद्र पार करते हैं, रेगिस्तानों में बिना भोजन-पानी के चलते हैं, जंगलों से गुजरते हैं या मानव तस्करों पर निर्भर होते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं। यौन हिंसा, जबरन श्रम, फिरौती, अपहरण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यह संकट केवल अपराधी गिरोहों का परिणाम नहीं, बल्कि उन नीतिगत व्यवस्थाओं का भी नतीजा है, जो सुरक्षित प्रवासन के अवसर उपलब्ध नहीं करातीं। प्रवासन मामले में जब कानूनी रास्ते बंद होते हैं, तो अवैध संजाल फलते-फूलते हैं।

प्रवासन का मानवीय प्रभाव सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया आयाम है। किसी प्रवासी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। वह पूरे परिवार की आर्थिक संरचना को तोड़ देती है। अनेक परिवार अपने सदस्य को विदेश भेजने के लिए ऋण लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं या जीवन भर की बचत लगा देते हैं। यदि वही व्यक्ति यात्रा में लापता हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है, बुजुर्गों की देखभाल रुक सकती है और परिवार की आय समाप्त हो सकती है। लापता होने की स्थिति और भी पीड़ादायक होती है, क्योंकि परिजन वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। महिलाओं पर इसका बोझ अधिक पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है।

प्रवासी महिलाओं की स्थिति और भी जटिल होती है। घरेलू काम, देखभाल सेवा या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबा कार्य समय, यौन उत्पीड़न और कानूनी सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है।

देश का नया अन्न भंडार बनता मध्यप्रदेश

पंजाब-हरियाणा के वर्चस्व को चुनौती, किसान हितों की नई राजनीति गढ़ रहे डॉ.मोहन यादव

कृष्णमोहन झा

देश में जब भी सरकारी गेहूं खरीदी की चर्चा होती थी तो सबसे पहले पंजाब और हरियाणा का नाम लिया जाता था। हरित क्रांति के बाद इन दोनों राज्यों ने दशकों तक देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ के रूप में अपनी भूमिका निभाई। बाद के वर्षों में राजस्थान और उत्तरप्रदेश भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने, लेकिन आज जिस राज्य ने सबसे तेज़ी से अपनी स्थिति मजबूत की है, वह मध्यप्रदेश है।

10 मई 2026 तक मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के जो आंकड़े सामने आए हैं, वे केवल प्रशासनिक सफलता की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह संकेत भी देते हैं कि प्रदेश अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का नया केंद्र बनता जा रहा है।

अब तक राज्य में 14 लाख 82 हजार 865 स्लॉट आरक्षित किए जा चुके हैं। 10 लाख 959 किसानों ने अपनी उपज बेची है। कुल 63 लाख 19 हजार 675 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। राज्य की अधिकतम खरीदी क्षमता 1 करोड़ 22 लाख 28 हजार 122 मीट्रिक टन तक पहुंच चुकी है। किसानों को अब तक 11 हजार 623 करोड़ 43 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। केवल एक दिन पहले ही *55 हजार 380 किसानों से 4 लाख 86 हजार 368 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।

इन आंकड़ों की तुलना यदि अन्य राज्यों से की जाए तो मध्यप्रदेश की उपलब्धि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। पंजाब में इस वर्ष लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और वह अभी भी देश में शीर्ष पर है। हरियाणा में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास खरीदी हो रही है। राजस्थान का लक्ष्य लगभग 21 लाख मीट्रिक टन है, जबकि उत्तरप्रदेश लगभग 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सरकारी गेहूं खरीदी बेहद सीमित है।

स्पष्ट है कि पंजाब के बाद यदि कोई राज्य सबसे तेज़ी से अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है तो वह मध्यप्रदेश है।

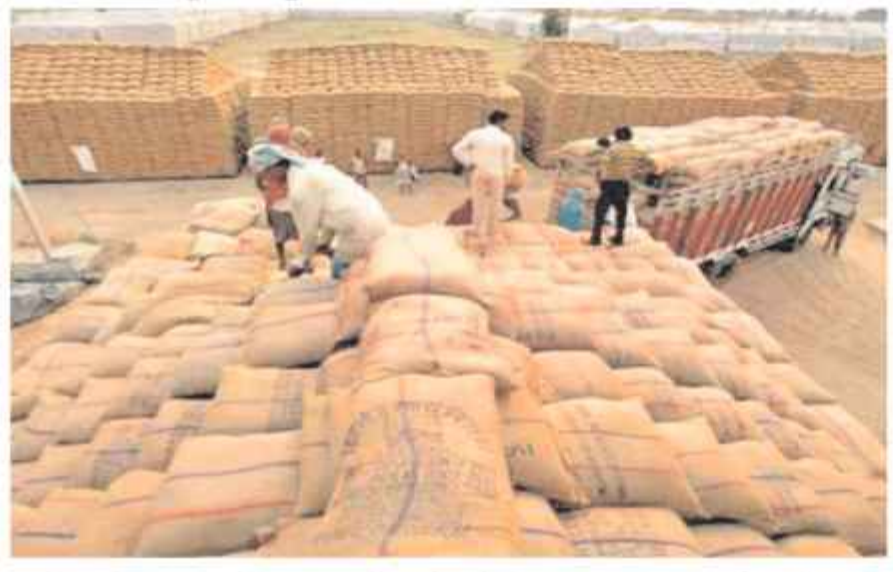

पहले केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के लगातार प्रयासों के बाद यह लक्ष्य बढ़ाकर एक करोड़ मीट्रिक टन* कर दिया गया। यह केवल आंकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार को मध्यप्रदेश की कृषि क्षमता और यहां की खरीदी व्यवस्था पर भरोसा है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री केवल बैठकों और घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं। वे लगातार खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। खरगौन के कतरगांव से लेकर शाजापुर के मकोड़ी तक उनका अचानक पहुंचना यह संदेश देता है कि सरकार किसान हितों के मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगी।

उन्होंने स्वयं तौल व्यवस्था देखी, बारदाने की उपलब्धता की समीक्षा की, किसानों से सीधा संवाद किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी अवधि बढ़ाने का निर्णय भी इसी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

यह सक्रियता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यप्रदेश वर्ष 2017 के मंदसौर किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को भूल नहीं सकता। उस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया था कि किसान केवल घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होता। उसे समय पर खरीदी, समय पर भुगतान और सम्मानजनक व्यवहार चाहिए।

मोदी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को बढ़ा हुआ खरीदी लक्ष्य दिया जाना और राज्य सरकार की लगातार जमीनी निगरानी यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय है।

आज जब कई राज्यों में किसान खरीदी व्यवस्था को लेकर शिकायत कर रहे हैं, तब मध्यप्रदेश एक सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है। यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश केवल देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सरकारी गेहूं खरीदी राज्य भी बन सकता है।

यह केवल कृषि क्षेत्र की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व की एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक सफलता के रूप में भी दर्ज होगी।

तुलसी की माया

पूरी कॉलोनी में तुलसी के काम की चर्चा बनी रहती। कालोनी की सभी महिलाएं चाहतीं, तुलसी मेरे घर काम करने लगे। पर वाह रे तुलसी, महीने में छः दिन का गोल ऐसे ही मार देती।

कभी -कभी महीने में छः दिन ही काम पर आती तब भी कोई उसे अपने घर से काम से अलग नहीं करता।

छुट्टी मारने की उसकी अदा को कोई भांप नहीं सकता। उसकी हर चाल में सम्मोहन रहता जो सीधे घर मालकिन पर ही असर करता। किसी भी घर के पुरुष की यह हिम्मत नहीं रहती कि तुलसी के विपरीत दो शब्द कंठ से निकल जाए।

इन सब के बावजूद कॉलोनी में तुलसी का आकर्षण बना रहता। उसमें कोई विशेष योग्यता नहीं फिर भी अपने व्यवहार के कारण वह लोकप्रिय हो चुकी थी। उसके मीठे बोल सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते। जीवन उतार -चढ़ाव का ही नाम है। किसी रूप में धन कमाने की चाहत हर व्यक्ति में निहित रहना मनुष्य की जीवंत प्रवृत्ति का हिस्सा है। इसी चाह में तुलसी एक कम्पनी में अभिकर्ता बनती है और बिजनेस चैनल बनाने को आतुर हो जाती है। अब वह उसी कार्य में व्यस्त रहने लगी। अपने सगे, परिचितों से मिलकर अपनी आय को बढ़ाने की जद्दोजहद में कॉलोनी में बनी उसकी साख पर विपरीत प्रभाव होने लगा। वह कहीं - कहीं कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने का यत्न करने लगी थी।पहले उसकी स्फूर्ति, मीठे बोल और किसी काम को ना नहीं कहने की उसकी प्रवृत्ति उसकी खूबसूरती थी, जिसकी कायल कॉलोनी की हर महिला थी। तुलसी अब जीवन की ढलती शाम की तरह हो चुकी थी।

वही तुलसी जिसकी माया हमेशा बनी रही, वह धीरे -धीरे विलुप्त होने लगी। व्यावहारिक रूप में उसकी साख समाप्त हो चुकी थी। लोग व्यक्ति का वही रूप पसंद करते हैं, जो उनके लिए सुविधाजनक होता है।

गजेंद्र बख्शी
रिद्धि- सिद्धि कॉलोनी
राजनांदगांव

बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत आयोजित शिविर में योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीणों से की अपील

भानुप्रतापपुर। कभी भय और लाल आतंक की आगोश में रहने वाले ग्राम पंचायत सितरम के लिए का दिन बड़ा खुशनुमा रहा। दुर्गम और बीहड़ क्षेत्र में नारायणपुर जिले की सरहद से लगी ग्राम पंचायत सितरम में जिले के कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई और उनकी बहुप्रतीक्षित समस्याओं की जानकारी ली। बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत सितरम में शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी आज सुबह लगभग 11 बजे 6 से 7 किलोमीटर कच्चे मार्ग से होते हुए ग्राम सितरम पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया। जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी प्रसन्न और गदगद हुए। कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच कुसुम पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कई दशकों तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहा जिसकी वजह से ग्रामीण विकास से वंचित रहे। चूंकि अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है शासन की मंशानुसार प्राथमिकता से विकास कार्यों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन होगा। उन्होंने बताया कि बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 14 आधारभूत अधोसंरचनाओं और 31 व्यक्तिमूलक योजनाओं के शत प्रतिशत संतृप्तिकरण का कार्य किया जाएगा, जब तक प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ न मिल जाए। कलेक्टर ने कहा कि लंबे अरसे तक माओवाद का दंश झेल रहे ग्रामीणों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र आदि बनाए जाएंगे तथा ग्रामीणों को विकास से जोड़कर योजनाओं का लाभ दिलाने प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने परलकोट के शहीद गैंद सिंह परिसर में सामुदायिक भवन, घोटुल भवन तथा क्षेत्र की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर क्षीरसागर ने ग्रामीणों से बारी-बारी से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और यथासंभव कार्रवाई कर निराकरण करने की बात कही। कलेक्टर ने परलकोट के शहीद गैंद सिंह के स्मारक का अवलोकन किया तथा प्राचीन दंतेश्वरी माई मंदिर में जाकर जिलावासियों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान ग्राम पंचायत सितरम के सरपंच गणेश नायक ने राजस्व तथा वन भूमि का सीमांकन कराने और नारायणपुर जिले में आने वाली वन भूमि को कांकेर जिले में सम्मिलित करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को परस्पर समन्वय के साथ चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरपंच ने राजा मुंडा शाला भवन, प्री मेट्रिक छात्रावास, देवगुड़ी निर्माण, सर्व समाज सामुदायिक भवन, स्वागत द्वार निर्माण, हाई मास्ट सोलर लाइट, मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण, सौसी रोड निर्माण, वन अधिकार पट्टा इत्यादि मांगों से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सितरम के आश्रित ग्राम राजामुंडा, शेरमुंडा, छिंदपदर और कोंगे है एवं 254 परिवार तथा जनसंख्या 1169 है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां 121 आवास स्वीकृत हैं जिनमें से 08 पूर्ण हो चुके है। उक्त पंचायत में 262 जॉब कार्ड धारक है। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी, एसडीम पखांजूर मनीष देव साहू, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के सीईओ नाग सहित पुलिस एवं विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण मौजूद थे।

पंडरीपानी में सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों को मिली जनहितकारी योजनाओं की जानकारी

जगदलपुर। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बुधवार को जगदलपुर विकासखण्ड के ग्राम पंडरीपानी में सुशासन तिहार के तहत सुशासन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमिश्नर बस्तर डेमन सिंह ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर आम जनता द्वारा दिए गए आवेदनों और उनके निराकरण की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हुए अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। साथ ही भू-स्वामियों को डिजिटल किसान किताब, खसरा एवं बी-वन नकल प्रदाय करने और वनाधिकार मान्यता पत्रों का फौती-नामांतरण किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने प्रत्येक शिविर में स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा उन्हें उपचार सुविधाएं मुहैया करवाने कहा। साथ ही मोतियाबिंद जांच के लिए नेत्र सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित कर मोतियाबिंद पीड़ितों को जांच करने एवं जरूरत के अनुरूप जिला या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपरेशन से लाभान्वित किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने इन शिविरों में दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध करवाने कहा। वहीं आधार पंजीयन शिविर के माध्यम से मोबाइल नंबर सिंडींग करने एवं छूटे हुए ग्रामीणों का आधार पंजीयन करने के निर्देश दिए।

इस शिविर के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टाल पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सात महिलाओं को लाभान्वित किया गया, वहीं दूसरी ओर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए पांच बच्चों का अन्नप्राशन और छह गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म पूरी की गई। ग्रामीण आवास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्राम पंडरीपानी के धरमू और सुनकी को उनके नए सपनों के घर की चाबियाँ सौंपी गईं। किसानों को खेती-किसानी के लिए प्रोत्साहित करते हुए सहकारिता विभाग ने सात किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए, जबकि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा रागी बीज, आम और ऑयलपॉम के पौधों का वितरण कर किसानों को नवाचार के लिए प्रेरित किया गया। मत्स्यपालन विभाग ने भी आजीविका विस्तार हेतु दो हितग्राहियों को जाल वितरित किए। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड और सिकलिन कार्ड जारी किए, जो ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच का काम करेंगे।

इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा 14 परिवारों को नए राशन कार्ड और राजस्व विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। शिक्षा और प्रतिभा के प्रोत्साहन देते हुए आदिवासी विकास विभाग के छात्रावासों में रहकर 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित करने वाले 11 मेधावी विद्यार्थियों का विशेष सम्मान किया गया। जो क्षेत्र के अन्य छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बना।

स्विमिंग प्रशिक्षण में खिलाड़ी ले रहे नि:शुल्क प्रशिक्षण

कोण्डागांव। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा जिला कोण्डागांव के आदेशानुसार जिले के छात्र-छात्राओं को नवीन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन समर कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। समर कैम्प का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के शैक्षणिक संवर्धन, कौशल निर्माण तथा उनके रचनात्मक एवं समग्र विकास को प्रोत्साहित करना है। जिला स्तरीय ग्रीष्मकालीन समर कैम्प का आयोजन 01 से 25 मई 2026 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में कनेरा रोड स्थित स्विमिंग पूल में बच्चों एवं खिलाड़ियों को निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। समर कैम्प में महिला एवं पुरुष प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को तैराकी की विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा के सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। नगर सेना के लाइफगार्ड्स द्वारा स्विमिंग पूल परिसर में लगातार निगरानी रखी जा रही है, जिससे प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समर कैम्प के माध्यम से बच्चों को खेल गतिविधियों से जोड़ने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रोत्साहन मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु इस प्रकार की गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

सही दवा, शुद्ध आहार- यही छत्तीसगढ़ का आधार पर सघन जांच अभियान

कोण्डागांव। छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में जिले में सही दवा शुद्ध आहार- यही छत्तीसगढ़ का आधार के थीम के अंतर्गत विभाग के द्वारा 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किया गया। जिसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं औषधि उपलब्ध कराना है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय कोण्डागांव में विभिन्न आईस क्रीम पार्लर एवं शॉप का निरीक्षण किया गया। आइसक्रीम पार्लर एवं दुकानों के निरीक्षण दौरान परिसर में साफ-सफाई बनाये रखने, फ्रीजर को स्वच्छ रखने एवं निर्धारित तापमान बनाए रखने, आइसक्रीम की एक्सपायरी नियमित रूप से जांचने, खाद्य पंजीयन प्रदर्शित करने तथा कंपनी को वापस किये जाने वाले कालातीत खाद्य पदार्थों को कालातीत खाद्य पदार्थ लेबल लगाकर अलग रखने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही खरीदी बिल व्यवस्थित सँधारित रखने, पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड एवं कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड संधारित रखने हेतु निर्देश दिए गए।

सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार' विषय पर चलाया गया जागरूकता अभियान

कांकेर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कांकेर द्वारा जिले में 'सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार' संबंधी 15 दिवसीय जागरूकता एवं जांच अभियान द्वारा चलाया गया। इस अभियान अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रकोष्ठ द्वारा जिले के विभिन्न औषधि एवं खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिले में जनजागरूकता एवं जांच अभियान के दौरान जिले में सुरक्षित, गुणवत्ता पूर्ण एवं मानक दवाओ व खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न औषधि प्रतिष्ठान थोक एवं खुदरा औषधि विक्रेता फार्मेसी चेन, वैक्सीन संधारण कोस्मेटिक एजेंसी तथा विभिन्न सेंटर, गन्ना जूस, साफ्ट ड्रिंक्स आइसक्रिम वेंडर्स डेयरी, होटल प्रतिष्ठानों चाट गुपचुप ढाबा, रेस्टोरेंट, बेकरी, आइसकैंडी आइसगोला विक्रेता आदि प्रतिष्ठानो का सघन जांच एवं जनजागरूकता कार्य किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अभिहित अधिकारी सुष्मित देवांगन ने बताया कि इस अभियान के दौरान विभिन्न औषधि प्रतिष्ठानों- 29 थोक एवं खुदरा मेडिकल स्टोर, 15 कॉस्मेटिक एजेंसी, 08 शासकीय एवं निजी अस्पताल में वेक्सीन एवं मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया। तथा कोटपा एक्ट के तहत स्कूलों के आसपास किराना दुकानों, पान ठेलों, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन पर चालानी कार्यवाई की गई तथा 5080 रूपये का चालान किए गए एवं 04 संचालकों को नोटिस जारी कर सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस अभियान के दौरान 50 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठान जिसमें फल कोल्ड स्टोरेज, विक्रेता, हॉस्पिटल कैंटीन, डेयरी युनिट, मोमोस सेंटर, गुपचुप चाट सेंटर, आइसक्रीम पार्लर, बिरयानी सेंटर किराना दुकान, स्वीट्स शॉप, कैफे एण्ड रेस्टोरेंट आदि खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक सुधार हेतु निर्देशित किया गया। 05 फर्म को तत्काल सुधार हेतु नोटिस जारी किया गया। अल विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिया कि फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किसी भी स्थिति में न करें। अभियान के तहत विक्रेताओं को ग्लब्स, कैप एवं साफ सुथरे बर्तनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया तथा स्वच्छ पेयजल के

बांसला के जंगलों में 'भ्रष्टाचार' या 'चोरी', वन विभाग के दो अधिकारियों के बयानों ने खोली व्यवस्था की पोल

भानुप्रतापपुर। वन मंडल भानुप्रतापपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम बांसला के जंगलों में संरक्षित वन क्षेत्र में एएनआर कार्य के नाम पर एक बड़ा खेल सामने आया है। मीडिया के टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग और लगातार खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला करोड़ों के वन संरक्षण और फेंसिंग कार्य में बरती गई अनियमितता से जुड़ा है। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत मुख्य वन संरक्षक कांकेर से की गई है। अब देखना यह होगा कि क्या विभाग के उच्च अधिकारी अपने ही मातहतों के विरोधाभासी बयानों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर कोई निष्पक्ष जांच करते हैं या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा। ग्राम बांसला के जंगलों में कूप कटाई के बाद छोटे पौधों को संरक्षित करने के लिए फेंसिंग का कार्य किया जाना था। आरोप है कि मटेरियल सप्लायर को मार्च महीने में ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन मौके पर केवल आधा मटेरियल ही गिराया गया। बाकी बची हुई राशि के गबन की पूरी तैयारी थी, लेकिन मीडिया की सक्रियता ने इस योजना पर पानी फेर दिया। खबर प्रकाशित होते ही आनन-फानन में रातों-रात मटेरियल गिराकर अधूरे फेंसिंग कार्य को दोबारा शुरू कराया गया है। मुख्यालय और डिवीजन कार्यालय की नाक के नीचे जब करोड़ों की हेराफेरी और विरोधाभासी बयानों का खेल चल रहा है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि दुर्गुकोंदल, अंतागढ़ और आमाबेड़ा जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में व्यवस्था का क्या हाल होगा?

अधिकारियों के बयानों में फंसा पेंच: कौन सच, कौन झूठ?

इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाली बात वन विभाग के दो जिम्मेदार अधिकारियों के विरोधाभासी बयान है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। एडीएफओ पूर्व वन मंडल भानुप्रतापपुर ऋषभ जैन का कहना है कि फेंसिंग का कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन लगभग 100 मीटर फेंसिंग चोरी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि यदि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी संपत्ति चोरी हुई, तो क्या विभाग ने संबंधित थाने में इसकी एफआईआर दर्ज कराई? डिप्टी रेंजर मोनीष मण्डावी का बयान: इसके ठीक उलट, डिप्टी रेंजर का कहना है कि फेंसिंग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ था। आधा कार्य बचा था जिसे अब किया जा रहा है। उन्होंने चोरी की किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। एक ही विभाग के दो अधिकारी एक ही स्थान और कार्य को लेकर अलग-अलग जानकारी क्यों दे रहे हैं? क्या 'चोरी' की कहानी भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए गढ़ी गई थी?

उच्च स्तरीय जांच की मांग

मीडिया की टीम द्वारा मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब यह स्पष्ट होता दिख रहा है कि मीडिया के दबाव में विभाग अपनी कमियों को सुधारने में जुटा है। हालांकि, सरकारी धन के दुरुपयोग और भुगतान के बावजूद कार्य अधूरा छोड़ने जैसे गंभीर विषयों पर कार्रवाई की दरकार है।

मुख्यालय के करीब यह हाल, तो अंदरूनी इलाकों में 'अंधेरगर्दी'

ग्राम बांसला का जंगल डिवीजन कार्यालय के बेहद करीब है, जहाँ मीडिया की पहुँच आसान है। यहाँ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए 'चोरी' की झूठी कहानी तक गढ़ दी।

कोण्डागांव में तीसरे दिन भी पेट्रोल-डीजल संकट जारी, अधिकांश पेट्रोल पंप रहे सूखे

कोण्डागांव। जिले में पिछले तीन दिनों से पेट्रोल और डीजल की किल्लत लगातार बनी हुई है। मंगलवार को भी जिला मुख्यालय कोण्डागांव में अधिकांश ईंधन केंद्र सूखे नजर आए, जिससे वाहन चालकों और आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं हो सका। केवल इंडियन ऑयल का दिनेश फ्यूल केंद्र सीमित मात्रा में ईंधन उपलब्ध करा रहा है। यहां दोपहिया वाहनों को अधिकतम 200 रुपये तक का पेट्रोल और डीजल वाहनों को अधिकतम 2,000 रुपये तक का डीजल दिया जा रहा है। ईंधन की कमी के कारण कई वाहन मालिक बिना पेट्रोल-डीजल भरवाए ही वापस लौटते दिखाई दिए। दिनेश फ्यूल केंद्र पर सुबह से ही लंबी कतारें लगी रहीं और लोगों को तेज धूप में एक से डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मर्दापाल सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे उपभोक्ताओं ने बताया कि वे 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर केवल ईंधन भरवाने के लिए कोण्डागांव पहुंचे हैं। सभी पेट्रोल पंपों का चक्कर लगाने के बाद उन्हें एकमात्र स्थान पर सीमित मात्रा में ईंधन मिल पा रहा है।

फिलहाल जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कब सामान्य होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। लगातार बनी इस स्थिति से आम नागरिकों, किसानों, परिवहन व्यवसायियों तथा दैनिक उपयोगकर्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं।

सुकमा की हुंकार: 100 साल का संकल्प और राष्ट्र निर्माण का शंखनाद

सुकमा। दक्षिण बस्तर की धरती, जो कभी संघर्षों के लिए जानी जाती थी, मंगलवार को 'राष्ट्र चेतना' के स्वर से गुंजायमान हो उठी। अवसर था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य जन गोष्ठी का। जहाँ तोंगपाल से कोंटा तक के प्रबुद्ध समाज ने जुटकर यह संदेश दिया कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा अब 'शून्य से शतक' के गौरवशाली पड़ाव पर पहुंच चुकी है।

संघ संगठन नहीं, राष्ट्र की जीवंत चेतना

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता टोपलाल वर्मा ने अपने संबोधन में वैचारिक गहराई के साथ संघ की 100 वर्षों की साधना को रेखांकित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय है। प्रत्येक स्वयंसेवक को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना होगा। हमारा लक्ष्य केवल संख्या बल नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन और सामाजिक समरसता के जरिए राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति सुनिश्चित करना है।

– टोपलाल वर्मा, प्रांत संघ चालक

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का संगम

गोष्ठी की शुरुआत किसी औपचारिक कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उत्सव की तरह हुई। कोंटा से आए स्वयंसेवक गिरीश कुमार के गीतों ने समूचे वातावरण में जोश भर दिया। इंजीनियर जीतन सिंह के प्रेरक वचनों ने बौद्धिक चिंतन की नींव रखी। कार्यक्रम में व्यापारियों से लेकर पत्रकारों और कलाकारों तक की उपस्थिति ने यह साबित किया कि राष्ट्र निर्माण में समाज का हर वर्ग सहभागी है।

क्यों खास रही यह गोष्ठी?

यह आयोजन पारंपरिक भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें 'जिज्ञासा समाधान सत्र' के माध्यम से जीवंत संवाद हुआ। लोगों ने राष्ट्र की वर्तमान चुनौतियों और संघ की भावी कार्ययोजना पर प्रश्न रखे, जिनका समाधान प्रमुख वक्ताओं ने सहजता से किया। सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी सीएल ठाकुर ने गायत्री प्रज्ञा पीठ के अनुभवों को साझा करते हुए सामाजिक परिवर्तन में संघ के योगदान को मील का पत्थर बताया।

वंदे मातरम् के साथ नई ऊर्जा

चमन लाल साहू के कुशल संचालन और दीपक बारसे के आभार प्रदर्शन के बाद, जब सामूहिक स्वर में वंदे मातरम का गान हुआ, तो वह केवल एक समापन नहीं, बल्कि सुकमा के विकास और राष्ट्र की अखंडता के लिए एक नए संकल्प की शुरुआत थी। बस्तर के हृदय स्थल से उठा यह राष्ट्रभाव का संदेश अब सुदूर वनांचलों तक नई जागृति लाने को तैयार है।

अतिसंवेदनशील रहे ग्राम पंचायत सितरम में कलेक्टर ने लगाई चौपाल

कांकेर। कभी भय और लाल आतंक की आगोश में रहने वाले ग्राम पंचायत सितरम के लिए खुशनुमा रहा। दुर्गम और बीहड़ क्षेत्र में नारायणपुर जिले की सरहद से लगी ग्राम पंचायत सितरम में जिले के कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई और उनकी बहुप्रतीक्षित समस्याओं की जानकारी ली। बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत ग्राम पंचायत सितरम में शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर क्षीरसागर और जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी आज सुबह लगभग 11 बजे 6 से 7 किलोमीटर कच्चे मार्ग से होते हुए ग्राम सितरम पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका परंपरागत ढंग से स्वागत किया। जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी प्रसन्न और गदगद हुए। कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच कुसुम पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कई दशकों तक नक्सलवाद के प्रभाव में रहा जिसकी वजह से ग्रामीण विकास से वंचित रहे। चूंकि अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है शासन की मंशानुसार प्राथमिकता से विकास कार्यों का जल्द से जल्द क्रियान्वयन होगा। उन्होंने बताया कि बस्तर मुन्ने और सुशासन तिहार के तहत यह शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 14 आधारभूत अधोसंरचनाओं और 31 व्यक्तिमूलक योजनाओं के शत प्रतिशत संतृप्तिकरण का कार्य किया जाएगा, जब तक प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की योजनाओं का लाभ न मिल जाए। कलेक्टर ने कहा कि लंबे अरसे तक माओवाद का दंश झेल रहे ग्रामीणों का राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जॉब कार्ड, वन अधिकार मान्यता पत्र आदि बनाए जाएंगे तथा ग्रामीणों को विकास से जोड़कर योजनाओं का लाभ दिलाने प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने परलकोट के शहीद गैंद सिंह परिसर में सामुदायिक भवन, घोटुल भवन तथा क्षेत्र की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार की स्वीकृति प्रदान की। कलेक्टर क्षीरसागर ने ग्रामीणों से बारी-बारी से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं और यथासंभव कार्रवाई कर निराकरण करने की बात कही। कलेक्टर ने परलकोट के शहीद गैंद सिंह के स्मारक का अवलोकन किया तथा प्राचीन दंतेश्वरी माई मंदिर में जाकर जिलावासियों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान ग्राम पंचायत सितरम के सरपंच गणेश नायक ने राजस्व तथा वन भूमि का सीमांकन कराने और नारायणपुर जिले में आने वाली वन भूमि को कांकेर जिले में सम्मिलित करने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को परस्पर समन्वय के साथ चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सरपंच ने राजा मुंडा शाला भवन, प्री मेट्रिक छात्रावास, देवगुड़ी निर्माण, सर्व समाज सामुदायिक भवन, स्वागत द्वार निर्माण, हाई मास्ट सोलर लाइट, मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण, सौसी रोड निर्माण, वन अधिकार पट्टा इत्यादि मांगों से कलेक्टर को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम पंचायत सितरम के आश्रित ग्राम राजामुंडा, शेरमुंडा, छिंदपदर और कोंगे है एवं 254 परिवार तथा जनसंख्या 1169 है। यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां 121 आवास स्वीकृत है जिनमें से 08 पूर्ण हो चुके हैं। उक्त पंचायत में 262 जॉब कार्ड धारक हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी, एसडीम पखांजूर मनीष देव साहू, जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के सीईओ नाग सहित पुलिस एवं विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण मौजूद थे। बारिश के दिनों में टापुनुमा ग्राम सितरम का जंगल माओवादियों का सुरक्षित ठिकाना था।

सिविल अस्पताल पखांजूर का और बेहतर ढंग से किया जाएगा कायाकल्प

कांकेर। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जिले के दूरस्थ पखांजूर क्षेत्र के दो दिवसीय प्रवास के दौरान सिविल अस्पताल सह मातृ शिशु अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने सिविल अस्पताल को और अधिक सुविधा संपन्न और सेवाओं में विस्तार करने के निर्देश खंड चिकित्सा अधिकारी को दिए। इस दौरान कलेक्टर ने विभिन्न वार्डों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से हालचाल जाना। कलेक्टर सिविल अस्पताल सह मातृ शिशु अस्पताल पखांजूर पहुंचे, जहां निर्माणाधीन कार्यों का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल के पीछे बनाए जा रहे प्रसाधन कक्ष का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश बीएमओ को दिए। तदुपरांत उन्होंने ओपीडी एवं आईपीडी महिला एवं पुरुष वार्ड, नर्सिंग स्टॉफ कक्ष, आपात चिकित्सा कक्ष, एक्स-रे विभाग, पोषण पुनर्वास केंद्र, लैबोरेटरी, एएनसी कक्ष सहित हमर लैब आदि कक्ष में जाकर सतत् निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों से चर्चा कर उनका हालचाल भी जाना। बीएमओ ने बताया कि वर्तमान में यहाँ अधिकतर वायरल फीवर से पीड़ित मरीज आ रहे है। कलेक्टर ने कहा कि पिछले प्रवास की तुलना में वर्तमान में काफी सकारात्मक सुधार हुए है, लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश भी है। साथ ही स्वच्छता पर और अधिक फोकस करने के साथ-साथ परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और गंदगी करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए भी बीएमओ को निर्देशित किया। उन्होंने 10 बेड वाले एनआरसी में बेड ऑक्यूपेंसी में वृद्धि करने और बेहतर सेवाएं मुहैय्या कराने के भी निर्देश दिए। इस दौरान नगर पंचायत पखांजूर के अध्यक्ष साहा, जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी, एसडीम पखांजूर मनीष देव साहू सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इसके पश्चात् कलेक्टर ने नगर पंचायत पखांजूर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रस्तावित मावा मोदोल कोचिंग संस्थान के लिए स्थल निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित लाइब्रेरी और बाजार शेड परिसर का भी अवलोकन किया।

संक्षिप्त समाचार

रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा एवं सामाजिक दायित्वों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अपराधों की रोकथाम तथा सामाजिक सरोकारों के निर्वहन हेतु विभिन्न विशेष अभियानों के अंतर्गत प्रभावी एवं सराहनीय कार्य किए गए हैं । 1. आपरेशन नारकोस- रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ट्रेनों एवं रेलवे परिक्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु लगातार रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा आपरेशन नारकोस के तहत अभियान चलाया जा रहा है, यात्री ट्रेनों पर विशेष निगरानी रखते हुए नशीले पदार्थों की जब्ती एवं तस्करो को गिरफ्तार किया जा रहा है, इस अभियान के तहत रेलवे सुरक्षा बल के तीनो मंडलों (बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर) में स्पेशल टास्क टीम बनाकर कार्यवाही की जा रही है, इस कार्य के लिए तीनो मंडलों में स्थित CIB (Crime Intelligence Branch) और SIB (Special Intelligence Branch) को एक्टिव किया गया है, वर्ष-2025 में ऑपरेशन नारकोश के तहत कुल- 63 मामलो में 78 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 713.522 चद्द., मूल्य 1.70 करोड़ के मादक पदार्थ की जब्ती की गई है तथा इसी तरह वर्ष-2026 में अब तक 38 मामलो में 60 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 572.729 चद्द., मूल्य 2.86 करोड़ के मादक पदार्थ की जब्ती कर विधिपूर्ण कार्यवाही की गयी है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा विगत वर्षो से लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम वर्ष 2025 एवं 2026 में अब तक ऑपरेशन नारकोश के तहत 4.56 करोड़ मूल्य के मादक पदार्थों को डिटेक्ट कर 138 आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिपूर्ण कार्यवाही की गई है ड्ढ इस अभियान के तहत उड़ीसा राज्य के तरफ से आने वाली ट्रेनों जैसे- 12843 पूरी-अहमदाबाद, 18477 उत्कल एक्सप्रेस, 12807 समता एक्सप्रेस, 58213 टिटलागढ़-बिलासपुर पैसेंजर, 12994 पूरी-गांधीधाम एक्सप्रेस में मुख्य रूप से फोकस कर ड्राइव एवं चेकिंग अभियान लगातार जारी रखा गया है ड्ढ

शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-03 कोच की सुविधा

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व अधिकाधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली गाड़ी संख्या 18030/18029 शालीमार-एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी-3 कोच की सुविधा अस्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है 7 यह सुविधा शालीमार से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18030 शालीमार-एलटीटी एक्सप्रेस में दिनांक 16 मई 2026 से 22 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी 7 इसी प्रकार एलटीटी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18029 एलटीटी-शालीमार एक्सप्रेस में दिनाँक 18 मई 2026 से 24 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी । इस सुविधा से इस गाड़ी में यात्रा करने वाले अधिकाधिक यात्री लाभान्वित होंगे ।

भू-जल संवर्धन कार्यों पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण 15 मई को

154 ग्रामों के सरपंच, सचिव, तकनीकी सहायक होंगे शामिल

बिलासपुर। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के 154 ग्रामों में वी वायर टेक्नोलॉजी एवं पोंड विथ इंजेक्शन वेल के माध्यम से भू-जल संवर्धन कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन 15 मई को सवेरे 10 बजे से पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह शनिचरी बाजार में किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में चारों विकासखण्डों के संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव तथा जनपद पंचायतों के सभी उप अभियंता, तकनीकी सहायकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों को उक्त प्रशिक्षण में निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।

स्वास्थ्य केंद्रों में चलाया जा रहा टीकाकरण अभियान

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बढ़ी जागरूकता

यू-विन पोर्टल के माध्यम से स्वयं पंजीकरण की सुविधा

बिलासपुर। जिले में किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान लगातार गति पकड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित इस विशेष अभियान के प्रति अब लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है। बड़ी संख्या में किशोरियां अपने अभिभावकों के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर एचपीवी वैक्सीन लगवा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे आने वाली पीढ़ी की बेटियों को गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है।जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में एचपीवी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इनमें पीएचसी बेलगहना, टेंगनमाड़ा, बेलतरा, लखराम, चकरभाठा, करगीकला, पचपेड़ी, सीपत, सीएचसी बिल्हा, कोटा, मस्तूरी, रतनपुर एवं तखतपुर सहित जिला अस्पताल बिलासपुर और अर्बन पीएचसी गांधी चौक, बंधवापारा, देवरीखुर्द एवं राजकिशोर नगर शामिल हैं। टीकाकरण के लिए यू-विन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभिभावक एवं पात्र किशोरियां घर बैठे पंजीकरण कर सकती हैं। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शुभा गढ़ेवाल ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में तेजी से बढ़ रही गंभीर बीमारियों में शामिल है, लेकिन समय पर एचपीवी वैक्सीन लगवाकर इससे काफी हद तक बचाव संभव है। उन्होंने अभिभावकों से अपनी बेटियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय में टीकाकरण कराने की अपील की है। साथ ही लोगों से अफवाहों और भ्रांतियों से दूर रहकर वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करने का आग्रह भी किया गया है। एचपीवी एक सामान्य वायरस है, जिसके कुछ प्रकार महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण बनते हैं। यह संक्रमण लंबे समय तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के शरीर में मौजूद रह सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरावस्था में लगाया गया एचपीवी टीका शरीर में वायरस के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है, जिससे भविष्य में कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एचपीवी वैक्सीन के लिए वही किशोरियां पात्र होंगी जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया हो लेकिन अभी 15वां जन्मदिन नहीं मनाया हो। आयु सत्यापन के लिए आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र अथवा माता-पिता द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र मान्य किए गए हैं। इसके साथ ही फिजिकल कॉनसेंट फॉर्म एवं ऐज डिक्लेरेशन फॉर्म भरना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है। आशा कार्यकर्ता, मितानिन और स्वास्थ्य कर्मचारी घर-घर जाकर अभिभावकों को टीके के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में पहुंच रहे अभिभावकों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के जागरूकता अभियान के बाद अब वे इस वैक्सीन की उपयोगिता को समझ रहे हैं और अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए टीकाकरण को जरूरी मान रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन की राज्य सलाहकार ने किया स्वच्छता कार्यों का निरीक्षण.....

■ कचरा संग्रहण व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर

बिलासपुर। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की राज्य सलाहकार मोनिका सिंह द्वारा आज जनपद पंचायत तखतपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत निगारबंद, राजाकापा, बहुरता, पूरा एवं हरदी में सामुदायिक शौचालय तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वच्छग्राहियों द्वारा किए जा रहे श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने घर-घर कचरा संग्रहण कार्य में संलग्न स्वच्छाग्राही समूह के सदस्यों से स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। साथ ही ग्राम सरपंचों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वाले व्यक्तियों को पहले समझाइश दी जाए तथा इसके बाद भी सुधार नहीं होने पर जुर्माने का प्रावधान लागू किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि कचरा फैलाने वालों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत की टीम, सरपंच, सचिव, स्वच्छग्राही एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। साथ ही ग्रामीणों से गीले एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने एवं प्रबंधन को लेकर संवाद किया गया।

18 से 25 मई तक चलेगा जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान

कलेक्टर ने तैयारियों की समीक्षा की

बिलासपुर। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्देशानुसार जिले में 18 मई से 25 मई 2026 तक जनजातीय गरिमा उत्सव जन भागीदारी अभियान संचालित किया जाएगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अभियान के सफल संचालन, जनजागरूकता गतिविधियों एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग श्री सोनमणि वोरा द्वारा भी अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के तहत जनजातीय समुदायों तक शासन की योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जनसुनवाई, शिकायत निवारण एवं जागरूकता कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन कर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत विभिन्न शिविरों, जनसुनवाई कार्यक्रमों एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आयोजित कार्यक्रमों की दैनिक प्रगति रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ्स निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी विभागों को अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने तथा शासन की मंशानुरूप कार्यक्रमों का लाभ आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

महाप्रबंधक द्वारा आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे,बिलासपुर में आधारशिला विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न

बिलासपुर। श्री तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आज दिनांक 14 मई 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर स्थित आधारशिला विद्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, अध्यक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) विशेष रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं पूजन के साथ किया गया। तत्पश्चात महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश द्वारा शिलापट्ट का अनावरण कर विद्यालय भवन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इसके बाद उन्होंने विद्यालय का अवलोकन किया तथा बच्चों द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण के संदेश को बढ़ावा देने हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महाप्रबंधक, अध्यक्षा एवं उपस्थित अधिकारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन (सेक्रो) द्वारा संचालित आधारशिला विद्यालय का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को समुचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विद्यालय में वर्तमान में कुल 20 बच्चे अध्ययनरत हैं। यहाँ बच्चों को विशेष शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें खेल-खेल में सीखने की प्रक्रिया, दृश्य-श्रव्य माध्यमों, चित्रों एवं वीडियो आदि का उपयोग किया जाता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में धैर्य एवं निरंतर अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाता है। विद्यालय में बच्चों को स्वयं भोजन करना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, अपनी भावनाओं एवं आवश्यकताओं को व्यक्त करना तथा दैनिक कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी पर निर्भर न रहें और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें। इस अवसर पर श्री आदित्य कुमार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी सहित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के सभी विभागाध्यक्ष, अधिकारीगण एवं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन की पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर में हिंदी कार्यशाला तथा कवि-गोष्ठी आयोजित

बिलासपुर। रेलवे भर्ती बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बिलासपुर के तत्वावधान में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं कवि-गोष्ठी आयोजित की गई। प्रथम सत्र में 'प्रशासनिक शब्दावली' विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए । कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में कवि-गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर के महाप्रबंधक कार्यलय, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय तथा रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से आमंत्रित कार्मिकों ने काव्य पाठ किया। इसके अतिरिक्त बिलासपुर, कोरबा, महासमुंद, दुर्ग एवं आसपास के नगरों से आए साहित्यकारों के द्वारा भी काव्य पाठ किया गया। अतिथियों के स्वागत के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अरविन्द्र कुमार मेश्राम/ प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर तथा श्री पीयूष गुप्ता/ अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर के द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप-प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम का संयोजन श्री सुजेश कुमार शर्मा, रेलवे भर्ती बोर्ड बिलासपुर के द्वारा किया गया। द्वितीय सत्र में कवि-गोष्ठी का संचालन श्री राकेश कुमार श्रीवास के द्वारा किया गया। इस क्रम में लगातार तीन घंटों तक लगभग चालीस साहित्यकारों ने काव्य-पाठ किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि अरविन्द्र कुमार मेश्राम/ प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निश्चय ही रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर में राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं तथा स्वयं काव्य पाठ करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में कवि-गोष्ठी के आयोजन की सुदीर्घ परंपरा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष पीयूष गुप्ता/ अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर ने अपने उद्बोधन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कविता हृदय की भावना होती है तथा उन्होंने आगे कहा कि भारत के संविधान में वर्णित राजभाषा संबंधित अनुच्छेदों तथा गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर में हिंदी कार्यशाला, साहित्यकारों की जयंती तथा कवि-गोष्ठी का नियमित आयोजन रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर में किया जा रहा है। इसी क्रम में आज की कार्यशाला तथा कवि-गोष्ठी का सफल आयोजन किया गया है। रेल कार्यालयों एवं क्षेत्र से आए समस्त साहित्यकारों का अभिनंदन किया गया तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। श्री यू. एस. एस. राव/ सहायक सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर के द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में रेलवे भर्ती बोर्ड, बिलासपुर के समस्त कार्मिकों ने सक्रिय सहभागिता निभाई ।

जिले के तखतपुर ब्लॉक के हरदी में समाधान शिविर हरदी में 277 आवेदनों पर हुई सुनवाई

हितग्राहियों को मौके पर मिला विभिन्न योजनाओं का लाभ

बिलासपुर। जिले के तखतपुर ब्लॉक के हरदी में आज जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप के मुख्य आतिथ्य में सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया गया। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये स्टॉलों में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली। शिविर के माध्यमों से आज कुल 277 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में जनपद पंचायत अध्यक्ष डॉ. माधुरी वस्त्रकार, जनपद पंचायत सभापति, जनपद पंचायत सदस्य, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह, सरपंचगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती ललिता संतोष कश्यप ने कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन की योजनाएं तेजी से आमजन तक पहुंच रही हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से हो रहा है। जनपद पंचायत अध्यक्ष डॉ. माधुरी वस्त्रकार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जनकल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। लोगों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शासन द्वारा सुशासन तिहार अंतर्गत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने शिविर उपस्थित होकर अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लेने की अपील ग्रामीणों से की। राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत आमजनों की समस्या की सुनवाई और निराकरण हो रहा है। शिविर में आज 5 हितग्राहियों को राशनकार्ड, 8 को पेंशन स्वीकृति, 12 को मनरेगा जॉब कार्ड, 30 को आयुष्मान कार्ड, 40 को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस, 70 का बी.पी. एवं शुगर जांच, 30 का सिकल सेल जांच, 80 का स्वास्थ्य परीक्षण, 10 को आवास स्वीकृति एवं 5 समूह को 30 लाख का चेक वितरण, 72 को पट्टा वितरण, शिशुओं का अन्नप्राशन एवं महिलाओं का गोद भराई का कार्यक्रम किया गया।

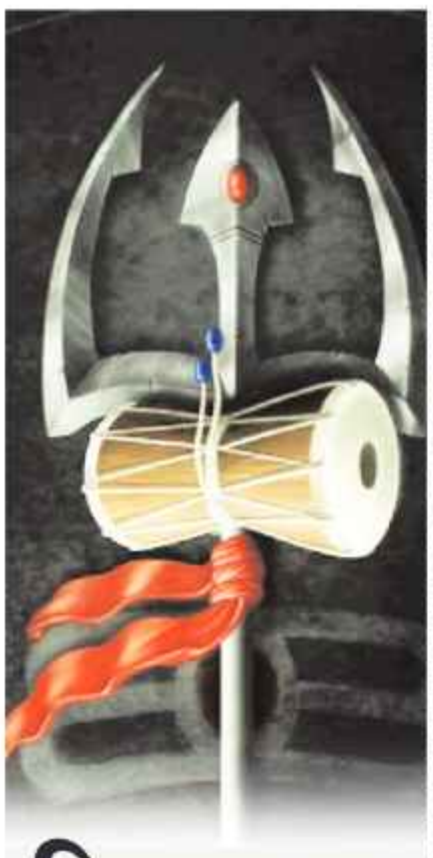

त्रिशूल पर लाल कपड़ा क्यों बांधते हैं?

अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर शिवालय में भगवान शिव के प्रतीकों की स्थापना की जाती है। भगवान शिव के यूं तो कई प्रतीक हैं, लेकिन मुख्य रूप से हर शिव मंदिर में आपको त्रिशूल रखें अवश्य दिख जायेंगे।

शिव मंदिर में या तो त्रिशूल की स्थापना होती है या फिर त्रिशूल रखने का विशेष स्थान बनाया जाता है। वहीं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो शिवालय में गढ़े या रखे त्रिशूल पर लाल रंग का कपड़ा बांधा जाता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य से आइये जानते हैं कि क्यों लाल कपड़े को त्रिशूल पर लपेटा जाता है और क्या है इसका महत्व।

ऐसा माना जाता है कि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से है और मंगल ग्रह की उत्पत्ति भगवान शिव की मुस्कान से हुई है। ऐसे में भगवान शिव के पुत्र के समान ही माने जाते हैं मंगल ग्रह। पौराणिक कथा कहती है कि मंगल ग्रह ने घोर तप करके भगवान शिव के समीप रहने का वरदान मांगा था। भगवान शिव ने जब मंगल ग्रह से कहा कि ग्रहों के चक्र से वह दूर हैं तो ऐसे में कैसे किसी ग्रह को वह अपने साथ रख सकते हैं तब मंगल ने भगवान शिव से आग्रह किया था कि मगल के किसी प्रतीक को वह अपने किसी प्रतीक से जोड़ दें। तब शिव जी ने लाल रंग को अपने त्रिशूल से जोड़ा। भगवान शिव ने लाल रंग का कपड़ा लेकर अपने त्रिशूल से बांधा और तभी से यह प्रथा बन गई कि त्रिशूल पर लाल कपड़ा बांधा जाए। हालांकि ज्योतिष में इसका महत्व इस रूप में माना जाता है कि लाल रंग का कपड़ा त्रिशूल पर बांधने से मंगल ग्रह मजबूत होता है और दोष दूर हो जाता है।

गृह प्रवेश करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का सही होना बेहद जरूरी

नया घर खरीदना जीवन में नए अध्याय जैसा होता है। वहीं नए घर में जाने के लिए सही समय और विधिवत पूजा करने का विधान है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का आगमन होता है।

हिन्दू धर्म में गृह प्रवेश बेहद महत्वपूर्ण और शुभ अनुष्ठान माना जाता है। गृह प्रवेश यानी कि नए घर में प्रवेश करने से पहले पूजा-पाठ करना। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख-समृद्धि का भी आगमन होता है। वहीं गृह प्रवेश करने के लिए ग्रह-नक्षत्रों का सही होना बेहद जरूरी है। गृह प्रवेश के माध्यम से भगवान गणेश और ग्रह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इससे घर में किसी प्रकार को कोई परेशानी नहीं आती है। ग्रह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का होना अत्यंत जरूरी है। ग्रह प्रवेश के दौरान कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी नहीं मिल पाते हैं। अब सवाल है कि बिना पंडित जी के गृह प्रवेश कैसे किया जाए। आइए विस्तार से जानते हैं।

बिना पंडित के इस विधि से करें गृह प्रवेश

- सबसे पहले कलश स्थापना करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कलश में गंगाजल, चावल, सुपारी और एक रुपया भरें। नारियल को दो भागों में काटकर कलश के दोनों तरफ रखें।
- पश्चात सबसे पहले भगवान गणेश और कुलदेवता की पूजा करें।
- उसके बाद नौ ग्रहों, वास्तु देवता और ग्रह देवता की पूजा करें।
- पूजा करने के बाद आरती गाएं।

गृह प्रवेश के लिए सामग्री

- गंगाजल
- स्वस्तिक बनाकर रखने के लिए लाल रंग
- धूप • दीपक • फूल • फल
- मिठाई • नारियल • चावल
- सुपारी • कलश • घी
- कुमकुम • हल्दी • पान

गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त

अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो शुभ मुहूर्त के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में गृह प्रवेश किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर के मध्य भाग से 24 मिनट पहले शुरू होता है और 24 मिनट बाद समाप्त होता है। इसका मतलब है कि यह दिन के मध्य भाग में होता है।

गृह प्रवेश के लिए क्या है नियम?

- सबसे पहले सभी पूजन सामग्री को लेकर दाहिने पैर से घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश करते समय घर की महिलाओं को नारियल फोड़कर अंदर ले जाना चाहिए।
- नए घर मे प्रवेश करते समय ॐ मंत्र का जाप करें।
- पूजा घर में गंगाजल से छिड़काव करें।
- गंगाजल से छिड़काव करने के बाद भगवान गणेश का ध्यान करें।
- इस दौरान कीर्तन करना बेहद शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है।

नए घर में तुलसी का पौधा लेकर करें प्रवेश

जब भी आप नए घर में प्रवेश करें आपके लिए जरूरी है कि सबसे पहले तुलसी का पौधा लेकर ही प्रवेश करें। यही नहीं गृह प्रवेश के साथ ही तुलसी का पौधा भी स्थापित कर दें और उसकी नियमित पूजा करें जिससे समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है।

नए घर में करें हवन

अगर आप घर की कुशलता बनाए रखना चाहती हैं तो बहुत जरूरी है कि गृह प्रवेश के बाद घर में सभी लोग मिलकर एक बार हवन जरूर करें। हवन करने से धुएं के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में होता है और खुशहाली बनी रहती है। यदि आप हवन के साथ कपूर जलाते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा असर होता है और ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में मदद करता है। आपको नियमित रूप से आरती में कपूर का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी जाती है।

नए घर में प्रवेश करते समय आजमाएं ज्योतिष के ये उपाय

नए घर में प्रवेश करते समय आपके मन में कई सवाल होते हैं। नए घर में कैसा होगा आपका भविष्य? किस दिशा में कौन सी चीज रखनी चाहिए? आपको किस तरह की चीजों को घर में रखना चाहिए? यही नहीं नए घर में आप कौन से उपाय आजमाकर खुशहाली ला सकते हैं। ऐसे कई सवालों के जवाब आपको ज्योतिष में मिल सकते हैं।

नए घर में प्रवेश करना एक नई शुरुआत का संकेत होता है और यह घड़ी हर किसी के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। इस नई सफल यात्रा को शुभ बनाने के लिए, ज्योतिष विज्ञान बहुत उपयोगी हो सकता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त और तिथि का होना बहुत जरूरी माना जाता है। उस समय के अनुसार ज्योतिष उपाय करने से आप अपने नए अवसरों को सही दिशा में ला सकते हैं। ऐसे ही आपको ज्योतिष से जुड़े कुछ उपायों की आजमाने की सलाह भी दी जाती है जिससे नया घर आपके लिए शुभ साबित हो सके।

नए घर में प्रवेश के लिए करें शुभ मुहूर्त का चयन

नए घर में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। जब भी आप घर में प्रवेश करें आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए और मुहूर्त का विचार करके ही यहां प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष की मानें तो कुछ विशेष तिथियां और मुहूर्त ऐसे होते हैं जो आपके भविष्य के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं और नये घर के प्रवेश को और भी शुभ बना सकते हैं।

गृह प्रवेश पूजा है जरूरी

ऐसा माना जाता है कि कभी भी जब आप नए घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले गृह प्रवेश पूजा अवश्य करवाएं। गृह प्रवेश पूजा एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय है जो नए घर की सुरक्षा और शुभता बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। आमतौर पर यह पूजा घर के स्वामी द्वारा ही की जाती है। इसके लिए मुख्य रूप से गणपति पूजन किया जाता है जिससे सकारात्मकता बनी रहे।

गायत्री मंत्र का करें जाप

आप जब भी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, उस घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने के लिए लगातार तीन रविवार 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है और गायत्री मंत्र का जाप परिवार के लोगों को मानसिक शांति भी प्रदान करता है। यदि संभव है तो यह जाप घर के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर ही करना चाहिए।

घर की दक्षिण दिशा में लाल झंडा लगाएं

आप जब भी नए घर में प्रवेश करें ध्यान देने की जरूरत है कि आप घर की दक्षिण दिशा में लाल रंग का झंडा लगाएं। लाल रंग विजय और साहस का प्रतीक माना जाता है और यदि आप इस रंग का झंडा लगाते हैं तो यह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और घर के लोगों के बीच सामंजस्य बनाने में मदद करता है। इसके प्रभाव से घर के भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है।

नए घर के हर कोने की करें सफाई

आप जब भी नए घर में प्रवेश करें आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है कि घर का कोई भी कोना गंदा नहीं होना चाहिए। किसी भी कोने में मकड़ी के जले नहीं लगे होने चाहिए। ये जाले आपके घर के लिए नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकते हैं।

श्री राम ही नहीं, बालि और हनुमान जी भी कर सकते थे रावण का वध

यह सत्य है कि रावण का वध श्री राम के हाथों होना ही लिखा था, लेकिन रामायण में ऐसे दो योद्धाओं का भी वर्णन मिलता है जो रावण का वध करने में सक्षम थे।

जब पृथ्वी पर रावण का अत्याचार बढ़ने लगा था तब भगवान विष्णु के सांतवे अवतार के रूप में भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर जन्म लिया था। श्री राम ने एक-एक कर अपनी बाल्य अवस्था से ही दुष्टों का सहार करना शुरू कर दिया था और वह समय भी शीघ्र आया जब वनवास के दौरान श्री राम ने रावण का वध कर उसके दुराचार से सृष्टि को मुक्त किया। यह सत्य है कि रावण का वध श्री राम के हाथों होना ही लिखा था, लेकिन रामायण में ऐसे दो योद्धाओं का भी वर्णन मिलता है जो रावण का वध करने में सक्षम थे।

कौन-कौन कर सकता था रावण का वध?

रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण अति बलशाली था। रावण के पास अनेकों मायावी और आसुरी शक्तियां मौजूद थीं। रावण की हुंकार से क्या मनुष्य और क्या देवता, सभी थर-थर कांपते थे। रावण की असीमित शक्तियों और उसके मनुष्य के हाथों मरने के वरदान के कारण ही श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए। हालांकि रामायण में यह भी बताया गया है कि दो ऐसे योद्धा थे जिनसे रावण कांपता था। रावण उन योद्धाओं से उलझने से भी डरता था क्योंकि कहीं न कहीं रावण को भी पता था कि वह योद्धा उसका वध करने की ताकत रखते थे। वह योद्धा थे- देवराज इंद्र का पुत्र बालि और भगवान शिव के अंश हनुमान जी।

असल में बालि को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करने आएगा, उसका आधा बल बालि के अंदर समाहित हो जाएगा। ऐसे में एक अबर रावण युद्ध करने पहुंचा तब वह बालि से युद्ध में हर गया और बालि 10 दिनों तक उसे अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा। तब रावण बाल-बाल बचा था।

ठीक ऐसे ही हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार होने के कारण परम शक्तिशाली थे और भगवान शिव की शक्तियां उनमें समाहित थीं। इस बात से से रावण भी अनिभिज्ञ नहीं था। इसी कारण से रावण ने कभी भी सीधे-सीधे हनुमान जी से युद्ध नहीं किया था।

दुर्ग के इंदिरा मार्केट में 17.35 करोड़ की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मल्टीलेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स जहां 298 कारों के पार्किंग की होगी सुविधा, ट्रैफ्फिक समस्या से शहरवासियों को मिलेगी राहत।

फोटो : नाहीद शेख

प्रधानमंत्री के अपील को कुछ अधिकारी कर रहे नजरअंदाज, कलेक्टर से कार्यवाही की मांग

अपील के बाद महापौर रामू रोहरा ने छोड़ा शासकीय वाहन, ई-रिक्शा, स्कूटी का कर रहे उपयोग

वर्षों से नहीं हो रहा शासकीय वाहनों में लग रहे इंधन का ऑडिट, कई अधिकारी रोज चले जाते हैं गृहग्राम

धमतरी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल, डीजल की बचत करने, एक वर्ष तक सोना-चांदी नहीं खरीदने की अपील देशवासियों के नाम जारी किया गया है। धमतरी जिले में इसका पालन करने वाले नगर के प्रथम नागरिक महापौर रामू रोहरा ने उनकी इस अपील को तुरंत लागू करते हुए चार पहिया शासकीय वाहन को त्यागकर दोपहिया वाहन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि छग शासन के धमतरी जिले में पदस्थ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री के आव्हान को नजरअंदाज करते हुए शासकीय वाहनों को दौरा बताकर उसका निजी इस्तेमाल किये जाने की जानकारी प्राप्त हुई है जिससे छग शासन को अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। अनेक अधिकारी तो ऐसे है जो शासकीय वाहन से अपने समीपस्थ गृहग्रामों में जाकर वहां से सोमवार को सुबह वापस आते हैं और शासकीय दौरा बताकर लॉग बुक को भरते आ रहे हैं। जानकारी मिली है कि खाद्य विभाग, विद्युत विभाग, राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी का नाम प्रमुखता से सामने आया है। खाद्य विभाग में पदस्थ अधिकारी जो कई वर्षों से धमतरी जिले में पदस्थ है और शाम होते ही रोजाना अपने गृहग्राम चले जाते हैं। हालांकि शासकीय वाहन को ये एक पेट्रोल पंप में खड़े कर देते हैं और वहां से ये निजी वाहन में जाते हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि निजी वाहन में डलने वाले इंधन को शासकीय दौरे में समाहित कर देते हैं। वहीं विद्युत विभाग में पदस्थ अधिकारी भी प्रतिदिन अपने गृहग्राम से धमतरी मुख्यालय आना-जाना करते हैं और इसे भी शासकीय दौरा बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों के नाम एक अपील जारी करते हुए कहा है कि सोना, चांदी नहीं खरीदें, पेट्रोल, डीजल की कम से कम खपत करें। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल की भारी किल्लत होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह अपील देशवासियों से की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री के अपील को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के तमाम अधिकारियों को पेट्रोल, डीजल की

खपत कम करने का निर्देश जारी किया है। उसका पालन करते हुए महापौर रामू रोहरा ने अपनी चार पहिया वाहन को छोड़ दोपहिया वाहन से काम प्रारंभ कर दिया है। उसका जीता-जागता प्रमाण पिछले दिनों उन्होंने अनेक निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने सभी पार्षदों, अधिकारियों के साथ मिलकर ऑटो, ई-रिक्शा में बैठकर समस्त निर्माणाधीन स्थलों में जाकर उसकी गुणवत्ता की जानकारी ली। संभवतः यह शहर के पहले शख्स है जिन्होंने अपने प्रिय नेताओं के अपील का तुरंत पालन कर एक संदेश जिलेवासियों को दिया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर शासन के प्रतिनिधि के रूप में पदस्थ जिले के अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं और आज भी शासकीय वाहनों का उपयोग निजी कार्यों के लिये करते आ रहे हैं और पेट्रोल, डीजल की खपत बढ़ा रहे हैं। ऐसे अधिकारी पर लगाम लगाने के लिये किसी प्रकार का कोई निर्देश विभागीय स्तर पर जारी नहीं किया गया है। यही कारण है कि ऐसे अधिकारी शुक्रवार शाम से रविवार रात तक निजी कार्यों के लिये शासकीय वाहनों का उपयोग करते हैं और लॉग बुक में शासकीय दौरा दर्ज कर देते हैं। प्रत्येक माह लाखों रूपये के इंधन शासकीय वाहनों में दौरे के नाम पर खर्च होता है। साथ ही साथ कुछ अधिकारी निजी वाहनों को किराये में लेकर भी शासन को दोहरी हानि पहुंचा रहे हैं। इसकी वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है जबकि नियमतः लाखों रूपये के शासकीय कोष से भुगतान होने वाले इंधन की ऑडिट भी होनी चाहिये। लेकिन ऐसी प्रक्रिया नहीं होने से शासन को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों के हौसले बुलंद है। जिले के विद्युत विभाग अधिकारी के साथ साथ अन्य अधिकारियों द्वारा भी शासकीय वाहनों को अपने निजी कार्यों के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है और हजारों लीटर पेट्रोल, डीजल की खपत की जा रही है। ऐसे अधिकारियों के वाहनों के लॉग बुक को अचानक जांच करने पर यह त्रुटियां सामने आ सकती है। इसके लिये शासन स्तर को भी चाहिये कि ऐसे अधिकारी जो शासकीय वाहनों का उपयोग करते है, उसके लिये एक नीति निर्धारण किया जाना चाहिये।

शहर के जागरूक लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री साय से मांग की है कि वे प्रत्येक कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के दौरे की पल-पल की जानकारी लेकर निजी कार्यों में चलने वाली शासकीय वाहनों की जानकारी लें और जो अधिकारी ऐसा करते है, उनके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही किया जाये। खबर के मुताबिक धमतरी जिले की सीमा, उड़ीसा बॉर्डर तक स्थित है। इस क्षेत्र में पदस्थ अधिकारी ऐसे कार्यों में लिप्त देखे गये हैं। अलावा इसके धमतरी में भी ऐसे कुछ विभागों के अधिकारी है जो जिला प्रमुख से लुकाछिपी का खेल कर अपने निजी कार्यों में ऐसे वाहनों को इस्तेमाल कर रहे है। यहां यह बताना जरूरी है कि जिले में उपनिर्वाचन, सुशासन तिहार-2026 को लेकर कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने तमाम अधिकारियों को जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने की हिदायत दी है जिसके चलते अधिकांश अधिकारी इसका पालन कर रहे है परंतु कुछ अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे है जिससे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री साय के अपील का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है जिस पर लगाम लगाये जाने की मांग जागरूक नागरिकों ने की है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को लेकर महापौर रामू रोहरा से दूरभाष पर चर्चा किये जाने पर उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि संकट की घड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी के अपील का पालन करें। मोदी की अपील के बाद मैंने सर्वप्रथम निर्णय लिया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, तब तक मैं वाहन के बदले ई-रिक्शा या स्कूटी से निगम सहित अन्य निर्माण स्थलों में जाकर उद्घाटन, निरीक्षण करूंगा। रोहरा ने यह भी कहा कि युद्ध के चलते स्थिति असामान्य होने के कारण हर भारतीय का कर्तव्य है कि वे कम से कम इंधन का प्रयोग करें। साथ ही सोना, चांदी अत्यावश्यक न हो तो न खरीदें। साथ ही विदेश यात्रा भी न करें।

नीट परीक्षा के रद्द होने को सरयू साहित्य एवं सुधिजनों ने बताया छात्रों के साथ खिलवाड़

भाटापारा। चिकित्सा शिक्षा मे प्रवेश की महत्वपूर्ण परीक्षा कुछ वर्षों से निरंतर विवादों एवं अव्यवस्थाओं के घेरे मे घिरी हुई नजर आ रही है,जिसके चलते इस महत्वपूर्ण परीक्षा की गरिमा प्रभावित होने के साथ ही इसकी विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है जिसका खामियाजा पूरी तरह बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, परीक्षा मे अनियमितता एवं अव्यवस्था एक तरह से इस महत्वपूर्ण परिक्षा की परिपाटी बनती जा रही है जिसकी चरम परिणिति इस वर्ष परीक्षा पेपर लीक होने की आशंका के मद्देनजर परीक्षा रद्द होने के रुप मे नजर आ रही है। उपरोक्त भाव व्यक्त करते हुए नगर की रचनात्मक संस्था सरयू साहित्य परिषद एवं नगर के सुधिजनों द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम को अत्यंत दुर्भाग्यजनक एवं बच्चों के परिश्रम एवं प्रतिभा के साथ खिलवाड बताया गया है, उनका कहना है कि परीक्षार्थी परीक्षा की तैयारी के लिए एड़ी चोटी की मेहनत करते है उसके उपरांत परीक्षा के लिए दूरदराज के परीक्षा केन्द्रों मे तमाम तरह की असुविधा झेलते हुए पंहुचते है,उसके बाद परीक्षा का रद्द हो जाना मतलब पुनः उन्ही कवायदों की पुनरावृति सीधे तौर पर बच्चों के साथ खिलवाड एवं अत्याचार है, सवाल यही उठता है कि वर्ष दर वर्ष अनियमितता की झलक मिलने के बाद भी अब तक व्यवस्था मे कसावट एवं सुचिता क्यों नही आ पा रही है। इसके लिए सीधे तौर पर विभाग के प्रमुख जिम्मेदार है परिषद के प्रमुख सदस्यों जिनमे गौरीशंकर शर्मा, मुकेश शर्मा, हरिहर शर्मा, डॉ वाय पी सोनी राजकुमार यदु मोनू मानिक प्रसाद दुबे, गिरधर गोपाल शर्मा, दिनेश शर्मा आदि द्वारा जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गयी है।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन हेतु सामान्य प्रेक्षक नियुक्त

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों के आम एवं उप निर्वाचन मई 2026 के लिए जिला पंचायत धमतरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेन्द्र सिंह ठाकुर को गरियाबंद जिले के लिए सामान्य प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पंच के 15 पद एवं सरपंच के 1 रिक्त पद हेतु उप निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। जिसके लिए विकासखंड गरियाबंद के ग्राम पंचायत नांगाबुड़ा, विकासखंड देवभोग के ग्राम पंचायत माहूलकोट, विकासखंड छुरा के ग्राम पंचायत करकरा, रजनकट्टा, पीपरछेड़ी, सेम्हरा, पण्डीपानी गोंड़ तथा विकासखंड मैनपुर के ग्राम पंचायत हरदीभाठा, भेजोपदर, गुरजीभाठा (अ) वार्ड क्रमांक 7 एवं 8, सगड़ा, गुरजीभाठा (टी), बुड़गेलटप्पा, कोयबा एवं खरीपथरा में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं शिकायतें सामान्य प्रेक्षक के मोबाइल नंबर 94063-78849 पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिली राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा

बस्तर से बंगाल तक अद्भुत नेतृत्व कौशल के लिये अमित शाह का आभार : लक्ष्मी वर्मा

भाटापारा। दिल्ली प्रवास के दौरान राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने देश के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर विभिन्न समसामयिक, संगठनात्मक एवं जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की। यह भेंट अत्यंत आत्मीय एवं प्रेरणादायी वातावरण में सम्पन्न हुई, जिसमें राष्ट्रहित, सुशासन, संगठन की कार्यसंस्कृति एवं छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने पश्चिम बंगाल जैसे

लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण एवं जटिल राजनीतिक परिवेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय एवं पहली बार सरकार गठन हेतु अमित शाह को बधाई एवं शुभकामनाएं दी,वही उन्होंने असम एवं पुडुचेरी में मिली उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता के लिए भी उनका अभिनंदन करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह के कुशल नेतृत्व, संगठन की मजबूत कार्यशैली तथा राष्ट्रहित आधारित राजनीति की विजय बताया। लक्ष्मी वर्मा ने इस अवसर पर एक साधारण कार्यकर्ता एवं बूथ स्तर से संगठन में सक्रिय रूप से कार्य करने वाली कार्यकर्ता पर विश्वास व्यक्त कर राज्यसभा सांसद जैसे महत्वपूर्ण दायित्व हेतु चयन किए जाने पर अमित शाह के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता आधारित कार्यसंस्कृति, समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रति नेतृत्व के विश्वास एवं संगठन की लोकतांत्रिक परंपरा का जीवंत उदाहरण है। भेंट के दौरान बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी अभियान एवं उसके सकारात्मक परिणामों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। वर्मा ने कहा कि वर्षों से बस्तर के विकास में बाधक बने नक्सलवाद जैसे गंभीर संकट को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा दृढ़ इच्छाशक्ति एवं रणनीतिक नेतृत्व के साथ किए जा रहे प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं। इन प्रयासों से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, विश्वास एवं विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर आम जनता को मिल रहा है। वर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यों, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार, किसानों के हित, आदिवासी क्षेत्रों के विकास एवं प्रदेश की आम जनता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों से भी शाह को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य करने का संदेश दिया। लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व राष्ट्रहित, सुशासन, सुरक्षा एवं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण के प्रति पूर्णतः समर्पित है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के लिए निरंतर प्रेरणास्रोत है। इस भेंट एवं प्राप्त मार्गदर्शन को उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन के लिए अत्यंत प्रेरणादायी एवं ऊर्जा प्रदान करने वाला क्षण बताया।

सुप्रीम कोर्ट की अभिनव पहल : 'समाधान समारोह 2026' में ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी मिलेंगे मीडियेटर

31 मई तक करें आवेदन

नई दिल्ली / दुर्ग/ भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा आम जनता तक न्याय को सुलभ, सरल और सहभागी बनाने के लिए एक विशेष अभियान ÷समाधान समारोह, 2026÷ की शुरुआत की गई है। इस ऐतिहासिक पहल के समापन चरण में 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को देश की शीर्ष अदालत में एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने कमर कस ली है।अवकाश में भी होगी काउंसलिंगजिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पक्षकारों की सुविधा के लिए इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश (Summer Vacation) के दौरान भी मीडियेटर/मध्यस्थ लगातार उपलब्ध रहेंगे। ताकि छुट्टियों के दिनों का उपयोग कर आपसी सहमति और संवाद के जरिए लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।घर बैठे 'वर्चुअल' माध्यम से जुड़ने की सुविधाइस विशेष लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पक्षकारों को दिल्ली आने की अनिवार्यता नहीं होगी। आमजन और हितधारक अपनी सुविधानुसार प्रत्यक्ष (Physical) रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Virtual Mode) के माध्यम से जुड़कर अपने विवादों का निपटारा कर सकते है।आवेदन की अंतिम तिथि 31 मईइस अभियान का लाभ उठाने के लिए इच्छुक पक्षकार एवं अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर जाकर निर्धारित गूगल फॉर्म (Google Form) के माध्यम से 31 मई 2026 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

भाजपा सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने निरंतर कार्य कर रही : प्रवीण दुबे

धमतरी। भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ जिला धमतरी की कार्यसमिति गठन पश्चात महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय धमतरी में सम्पन्न हुई। बैठक में सहकारिता प्रकोष्ठ के कार्यसमिति सदस्यों, सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं भाजपा पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठनात्मक विषयों, सहकारिता गतिविधियों के विस्तार तथा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित नेताओं ने सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक मजबूत करने तथा सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीणों एवं आम नागरिकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं को संगठन की रीति-नीति के अनुरूप सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ संयोजक प्रवीण दुबे ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता और सामूहिक विकास का मजबूत माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। रायपुर संभाग संयोजक नेतराम निषाद ने कहा कि सहकारिता प्रकोष्ठ संगठन और समाज के बीच मजबूत कड़ी का कार्य करता है। उन्होंने कार्यसमिति सदस्यों से गांव स्तर तक संगठन को सक्रिय करने और सहकारिता से जुड़े लोगों के साथ सतत संवाद बनाए रखने का आह्वान किया। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश बैस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और प्रत्येक प्रकोष्ठ संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र किसानों एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भाजपा इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नेहरू निषाद ने कहा कि सहकारिता की भावना समाज में सामूहिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने एवं सहकारिता योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि भाजपा संगठन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा पर कार्य करता है। उन्होंने सहकारिता प्रकोष्ठ को संगठन की महत्वपूर्ण इकाई बताते हुए कार्यकर्ताओं से सेवा और समर्पण भाव से कार्य करने की अपील की। महापौर रामू रोहरा ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने संगठनात्मक मजबूती एवं जनहित के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ठाकुर शशि पवार, भाजपा जिला महामंत्री महेंद्र पंडित, राकेश साहू एवं सहकारी भारती प्रदेश मंत्री दयाराम साहू ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठनात्मक एकजुटता एवं सक्रियता पर बल दिया। बैठक में संयोजक रूपचंद साहू, सहसंयोजक अमर पटेल, तरूण साहू सहित बड़ी संख्या में कार्यसमिति सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। उक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी उमेश साहू द्वारा दी गई।

विक्षिप्त महिला ने फेंका हनुमान जी की मूर्ति

भाटापारा। सूचना मिला कि हटरी बाजार भाटापारा स्थित एक मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा को फेंक दिया गया है, कि सूचना पर थाना भाटापारा शहर का पुलिस बल तत्काल घटना स्थल पहुंचा। पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण पर पाया गया कि हनुमान जी का एक छोटा मंदिर है, जिसमें हनुमान जी की दो मूर्तियां स्थापित है, जिसमें दोनों मूर्तियों को अपने स्थान से हटाकर मंदिर में ही फेंक दिया गया है तथा मूर्तियों में पहने लंगोट कपड़े को भी अलग कर दिया गया है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा तुरंत मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिसमें एक विक्षिप्त महिला द्वारा मंदिर अंदर घुसकर हनुमान जी की प्रतिमा को फेंकना पाया गया है। तत्संबंध में हनुमान जी की प्रतिमा को फेंकने वाले आरोपी के रूप में विक्षिप्त महिला की पहचान हो गई है। पुलिस द्वारा उक्त विक्षिप्त महिला को माननीय न्यायालय के आदेश उपरांत मानसिक सुधार केंद्र सेंदरी बिलासपुर भेजने की प्रक्रिया की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक संजय तिवारी द्वारा असमा पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ग्रास मेमोरियल सेंटर के बाजू, जयस्तंभ चौक, रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित करवाकर व गदा चौक, फरीद नगर रोड स्वर्गीय तुलाराम मेमोरियल स्कूल के पास सुपेला भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-490023 से प्रकाशित। संपादक : संजय तिवारी, मो. 9200000214 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारा न्यायतीन क्षेत्र दुर्ग होगा। डाक पंजीयन क्रमांक- सीजी/दुर्ग/लोकतंत्र प्रहरी/2026-28, Email : loktantraprahrinews@gmail.com